भारतीय वैश्विक
परिषद्

SAPRU HOUSE PAPER

# भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच भावी एफटीए का आकलन

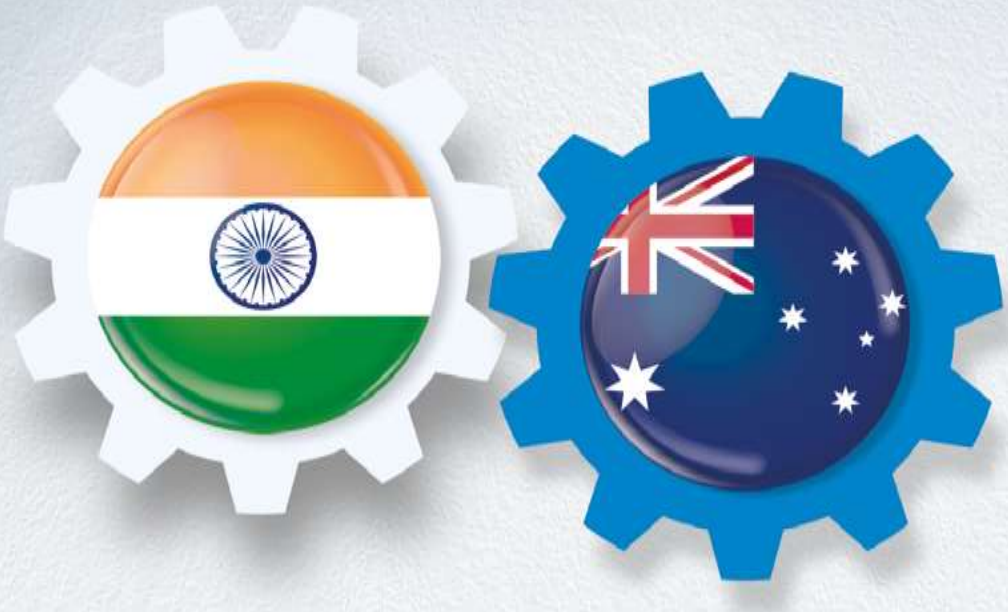

डॉ. राहुल नाथ चौधरी

विश्व मामलों की
भारतीय परिषद्

SAPRU HOUSE PAPER

# भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच भावी एफटीए का आकलन

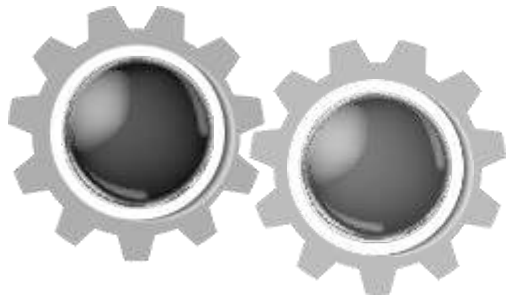

डॉ. राहुल नाथ चौधरी

Indian Council
of World Affairs

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ एचएन कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य निर्मित करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और सोच के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज आन्तरिक फैकल्टी के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान आयोजित करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों के द्वारा बौद्धिक गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करती है और कई प्रकार के प्रकाशन निकालती है। इसके पास पुस्तकों के बहुत अच्छे संकलन से भरपूर पुस्तकालय है, एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह इंडिया क्वार्टरली पत्रिका प्रकाशित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर समझ को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आई सी डब्ल्यू ए के अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हैं। परिषद की भारत में प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों के साथ भी भागीदारी है।

*भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच भावी एफटीए का आकलन*

पहली बार प्रकाशित,फरवरी 2023©

विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

ISBN: 978-93-83445-74-5

**सभी अधिकार सुरक्षित हैं। कॉपीराइट स्वामी की लिखित अनुमति के बिना, इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पुन: प्रस्तुत एक पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत, या प्रेषित,नहीं किया जा सकता है।**

**इस प्रकाशन में तथ्यों और विचारों की जिम्मेदारी विशेष रूप से लेखकों की है और उनकी व्याख्या विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के विचारों या नीति को आवश्यक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद,
सप्रू हाउस, बाराखंबा रोड
नई दिल्ली 110001, भारतT: +91-11-2331 7246-49 | F: +91-11-2331 1208

www.icwa.in

## विषय-सूची


परिचय ..... 5

साहित्य समीक्षा..... 5

व्यापार निर्माण और व्यापर परिवर्तन की अवधारणा ..... 8

क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीए) और भारत की संलग्नता ..... 9

बढ़ती भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी ..... 15

ऐतिहासिक संदर्भ ..... 16

सामरिक भागीदारी..... 17

चीन कारक..... 19

सांस्कृतिक संबंध..... 21

आईओआर में रक्षा और समुद्री सहयोग..... 22

ऊर्जा सहयोग..... 25

विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग ..... 26

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध ..... 30

व्यापार गहनता सूचकांक (टीआईआई) विश्लेषण..... 36

अध्ययन की पद्धति..... 39

अनुकरण परिदृश्य..... 42

परिणाम और चर्चा ..... 43

निष्कर्ष..... 48

संदर्भ ..... 53

अनुबंध..... 57

## परिचय

वैश्वीकरण की अवधारणा ने हाल के दिनों में नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। कोविड-19 के प्रसार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके बाद के प्रभावों ने खुली अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व को और स्थापित कर दिया है। देश तेजी से बहुपक्षीय और साथ ही साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े व्यापार समझौतों -क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) और ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) पर पिछले दो तीन वर्षों के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इन समझौतों पर हस्ताक्षर दो साल से भी कम समय के अंतराल में किए गए थे। अर्थव्यवस्थाएं पहले से कहीं अधिक दूसरों के साथ एकीकृत हो रही हैं। उनके अंतर्गत आने वाले व्यापार का वैश्विक हिस्सा पिछले डेढ़ दशक में लगातार बढ़ रहा है (अहमद, 2011)। "देश अधिमान्य या मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में संलग्न होने के विकल्प का पता लगाने के लिए अपने संभाव्य व्यापारिक भागीदारों की ओर रुख कर रहे हैं। भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत ने हाल ही में अपनी कई रुकी हुई एफटीए वार्ताओं को फिर से शुरू किया है। ऐसी ही एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है।

### साहित्य समीक्षा

विद्वानों के एक बड़े निकाय का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एफटीए दोनों देशों के लिए कई अवसर खोलेगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के कई पहलुओं की खोज करने वाले इस विषय पर महत्वपूर्ण संख्या में अध्ययन मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र दोनों के विद्वानों ने इस विषय को अपने-अपने परिप्रेक्ष्य से समझने का प्रयास किया। ऐसा ही एक अध्ययन पांडा और बरुआ (2010) द्वारा किया गया है। वे अनुशंसा करते हैं कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक संपूरकताएं रणनीतिक साझेदारी को मूर्त रूप देने की दिशा में प्रमुख चालक हैं। इन दोनों देशों के बीच प्रस्तावित एफटीए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने, अतीत में अनुभव की जा रही विकास गति का लाभ उठाने के लिए सहयोग करने का एक मूल्यवान अवसर प्रस्तुत करता है।

अहमद (2011) एक संगणनीय सामान्य संतुलन (सीजीई) मॉडल का उपयोग करके भावी भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए के संभावित आर्थिक प्रभावों की जाँच करता है। वह छोटी और लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए चार काल्पनिक टैरिफ उदारीकरण परिदृश्यों का उपयोग करता है। अध्ययन से पता चलता है कि वेलफेयर के मामले में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को लाभ होता है। अध्ययन आगे बताता है कि ऑस्ट्रेलिया का निर्यात तीव्रता सूचकांक आयात तीव्रता सूचकांक से अधिक है क्योंकि यह आयात की तुलना में भारत को निर्यात अधिक करता है। इसे सार रूप में ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलियाई बाजार का दोहन नहीं किया है और पारस्परिक हित में बाजार में अधिक पैठ हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए आवंटन क्षमता में व्यापक रूप से सुधार के लिए यह सुझाव देता है कि शुद्ध व्यापार सृजन किया जाए। अध्ययन, भावी भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए पर बातचीत करते समय भारत के हित में सर्वोत्तम रणनीति के रूप में आंशिक और चयनित टैरिफ उदारीकरण की सिफारिश करता है । भारत को ऑस्ट्रेलिया में अपने वित्तीय, सॉफ्टवेयर और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवा क्षेत्रों के लिए बाजार पहुँच प्राप्त करने के अलावा पेशेवरों के लिए आसान गतिशीलता और आसान वीजा मानदंडों की माँग करने पर लाभ होगा।

आलम एट. अल (2013) कृषि क्षेत्र के संदर्भ में प्रस्तावित भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए का विश्लेषण करते हुए टिप्पणी करते हैं कि कृषि व्यापार उदारीकरण भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक कठिन कार्य होगा। लेखकों का तर्क है कि जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है, उसे अपने कृषि क्षेत्र को और उदार बनाना चाहिए । अल्पावधि में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इससे आर्थिक सुधार में वृद्धि होने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए इस तरह के उदारीकरण को बढ़ावा दे सकता है और ऑस्ट्रेलिया के कृषि उत्पादकों को भारत में अपना निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकता है। कृषि में उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव अनिवार्य रूप से केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी इसके विस्तार की संभावना है।

चो और यून (2014) ने प्रस्तावित भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए के क्षेत्रीय प्रभाव का अध्ययन किया। स्थिर लागू सामान्य संतुलन मॉडल को लागू करना, और एक सामाजिक लेखा मैट्रिक्स का उपयोग करने से पता चलता है कि परिणाम अतीत में देखे गए व्यापार-उदारीकरण के अनुभवों के अनुरूप हैं, जो कहते हैं कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि से निर्यात क्षेत्रों में वृद्धि होती है और आयात क्षेत्रों में कीमतों में गिरावट आती है। उनके विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात मामूली रूप से बढ़ता है और ईंधन निर्यात में भारी रूप से केंद्रित हो जाता है, जबकि आयात में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो मूल रूप से अधिक संरक्षित थे।

ब्रूस्टर (2015) का तर्क है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध आर्थिक की तुलना में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि हिन्द-प्रशांत में शक्ति का बदलता संतुलन- और विशेष रूप से चीन और भारत दोनों का प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरना- भारत और ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षा और रक्षा मुद्दों पर एकसाथ होने के लिए मजबूर कर रहा है। ये दो देश तेजी से एक दूसरे को चीन के खिलाफ संतुलन करने पर केंद्रित एक उभरती हुई धुरी के ध्रुवों के रूप में देख रहे हैं। लेखक का तर्क है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों के लिए प्रमुख बाजार खोलने का इच्छुक होगा, हालांकि निवेश और सेवाओं में अधिक प्रगति की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑस्ट्रेलियाभारत सीईसीए-, यदि और जब भी संपन्न हो जाता है, तो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन इसके तात्कालिक आर्थिक महत्व के अपेक्षा राजनीतिक महत्व अधिक हो सकता है।

### व्यापार निर्माण और व्यापर परिवर्तन की अवधारणा[1]

विनर (1950) व्यापार निर्माण और व्यापार परिवर्तन की अवधारणाओं का परिचय देते हैं, दो विरोधी कल्याणकारी प्रभाव जो पीटीए के गठन के साथ आते हैं, और दिखाते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर व्यापार उदारीकरण का शुद्ध प्रभाव स्पष्ट रूप से सकारात्मक नहीं है । पीटीए व्यापार निर्माण में परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, अगर क्षेत्रीय समझौते के गठन के कारण सदस्य अक्षम घरेलू उत्पादकों से स्विच करते हैं और अन्य पीटीए सदस्यों के कुशल उत्पादकों से आयात करते हैं । इस मामले में, उत्पादन दक्षता और खपत दक्षता दोनों से दक्षता लाभ उत्पन्न होता है । दूसरी ओर, ट्रेड परिवर्तन तब होता है, जब पीटीए के कारण, सदस्य आयात को क्षेत्र के भीतर उच्च लागत वाले उत्पादकों की बजाए दुनिया के बाकी हिस्सों के कम लागत वाले उत्पादकों के लिए स्विच करते हैं। व्यापार विचलन न केवल भागीदार देशों बल्कि शेष विश्व के वेलफेयर को भी कम करता है।

विश्व बैंक (2000) का एक अध्ययन एक उदाहरण के साथ व्यापार परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। मान लीजिए कि एक साझेदार देश से आयातित सामान की लागत 105 डॉलर प्रति यूनिट है, बाकी दुनिया (आरओडब्ल्यू) से 100 डॉलर है और दोनों ही मामलों में एमएफएन शुल्क 10 डॉलर है, जिससे उपभोक्ताओं द्वारा क्रमशः 115 डॉलर और 110 डॉलर का भुगतान किया जाता है। इस स्थिति में, आयात स्पष्ट रूप से आरओडब्ल्यू से 110 डॉलर पर हैं। मान लें कि अब देश साझेदार के साथ एक पीटीए बनाता है और इस तरह की व्यवस्था के तहत इस सामान के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया जाता है जिससे कि भागीदार देश से आयात के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत गिरकर 105 डॉलर हो जाती है, जबकि आरओडब्ल्यू से आयात की कीमत अभी भी 110 डॉलर है।

---

1 यह खंड झा (2011) से लिया गया है

उपभोक्ता विकल्प स्पष्ट हैं: वे भागीदार देश की तरफ जाते हैं, 105 डॉलर में सामान खरीदते हैं और 5 डॉलर बचाते हैं। लेकिन सरकार को अब प्रति यूनिट 10 डॉलर का नुकसान होता है (वह राजस्व जो उसे आरओडब्ल्यू से आयात की प्रत्येक इकाई पर मिल रहा था), इसलिए देश के लिए शुद्ध प्रभाव 5 डॉलर का नुकसान है। इस प्रकार पीटीए ने वास्तविक आय को कम कर दिया है। यह व्यापार परिवर्तन का हानिकारक कल्याणकारी प्रभाव है।

क्या कोई विशेष पीटीए ट्रेड निर्मित कर रहा है या ट्रेड परिवर्तित कर रहा है? उत्तर, विनर के अनुसार , इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्व-पीटीए आपूर्तिकर्ता कौन था। डी मेलो और पनागरिया (1993) यूएस-मेक्सिको एफटीए के संदर्भ में जूता उत्पादन का एक अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर अमेरिका एफटीए के गठन से पहले अपने जूते का उत्पादन करता है और बाद में मैक्सिको में स्थानांतरित हो जाता है, तो मैक्सिकन जूता उत्पादक कम लागत वाले उत्पादक होने चाहिए और इसलिए यह एफटीए व्यापार पैदा कर रहा है: संघ और शेष विश्व का लाभ बढ़ता है। यदि दूसरी ओर, अमेरिका ने किसी अन्य देश से प्रारंभिक संतुलन में जूते का आयात किया, तो वह देश मेक्सिको की तुलना में जूते की कम लागत वाला उत्पादक होना चाहिए। इस प्रकार निम्न लागत से उच्च लागत स्रोत के लिए व्यापार परिवर्तन होता है क्योंकि एफटीए यूएस द्वारा मेक्सिको के लिए जूते की अपनी माँग को स्थानांतरित करने के बाद: संघ और दुनिया के लाभ में गिरावट आई है।

## क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरटीएएस) और भारत की संलग्नता

"आरटीए अब बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता के साथ-साथ लगभग सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार नीति उपकरण बन गए हैं। उरुग्वे दौर की वार्ताओं के दौरान आरटीए की संख्या के साथ-साथ उनके अंतर्गत आने वाले व्यापार के विश्व हिस्से में वृद्धि की प्रवृत्ति

देखी गई है और दोहा दौर में मौजूदा गतिरोध के संदर्भ में प्रस्तावित और बातचीत किए जा रहे कई आरटीए द्वारा इसे और मजबूत किया गया है।"

"आरटीए को, मोटे तौर पर दो या दो से अधिक देशों और/या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक दूसरे के साथ अधिमान्य व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए समझौते के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आरटीए अपने दायरे में काफी भिन्न हैं। अपने सरलतम रूप में, वे दो या दो से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच वस्तुओं की सीमित सीमा पर टैरिफ वरीयताओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था करते हैं, जिन्हें आमतौर पर अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (पीटीए) के रूप में जाना जाता है। दूसरे चरम पर, वे काफी हद तक व्यापार वाली वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से उदार बना सकते हैं और व्यापार के मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जो मानकों, सेवाओं, बौद्धिक संपदा, निवेश, गैर-टैरिफ बाधाओं, व्यापार सुविधा, प्रतियोगिता आदि जैसे क्षेत्रों में टैरिफ उन्मूलन के पारंपरिक दृष्टिकोण से काफी आगे तक फैले हुए हैं। "

"यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा एकल बाजार और उत्तर अमेरिकी देशों द्वारा उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) के गठन के बाद क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को 1990 के दशक में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अपनाया गया है। क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की बढ़ती विश्वव्यापी लोकप्रियता के साथ, आधे से अधिक विश्व व्यापार अब क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) (अर्थात, अधिमान्य आधार पर) के सदस्यों के बीच आयोजित किया जाता है, न कि सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर। उत्पादन और निवेश के वैश्विक पैटर्न को आकार देने में क्षेत्रीय एकीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है।

भारत हमेशा एक खुली, न्यायसंगत, पूर्वानुमेय, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय वार्ताओं में संलग्नताओं को प्रधानता देता है । हालांकि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि विश्व व्यापार में आरटीए लंबे समय तक जारी रहेगा, भारत अपने निर्यात बाजारों के विस्तार के इरादे से अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ जुड़ा हुआ है।"

प्रारंभिक चरण में, भारत ने क्षेत्रवाद के लिए एक सतर्क और संरक्षित दृष्टिकोण अपनाया और यह शुरू में मुख्य रूप से पीटीए के माध्यम से केवल कुछ द्विपक्षीय/क्षेत्रीय पहलों में शामिल था । इनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) में टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान करने के लिए 1975 में हस्ताक्षरित बैंकॉक समझौता (जिसे अब एपीटीए कहा जाता है), जी-77 सदस्य देशों के बीच टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान करने के लिए 1988 में हस्ताक्षर किए गए - व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी), और दक्षिण एशिया में व्यापार को उदार बनाने के लिए 1993 में हस्ताक्षर किए गए - सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (एसएपीटीए) - शामिल है । हालांकि, उत्पादों की सीमित कवरेज के कारण, इन अनुबंधों से सदस्य देशों के साथ व्यापार की मात्रा में वृद्धि के संदर्भ में सीमित परिणाम प्राप्त हुए हैं । भारत आरटीए को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पूरक व्यापार उदारीकरण के समग्र उद्देश्य की दिशा में 'बिल्डिंग ब्लॉक्स' के रूप में देखता है।

इस दशक के शुरुआती भाग से, भारत ने, कुछ मामलों में, माल में एफटीए को कवर करने वाले व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की ओर आगे बढ़ने की दृष्टि से समझौतों को पूरा करना शुरू किया। (अर्थात, महत्वपूर्ण व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर और संवेदनशील वस्तुओं की अपेक्षाकृत छोटी नकारात्मक सूची, जिन पर कोई या सीमित शुल्क रियायतें नहीं दी जाती हैं), सेवा, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य पहचाने गए क्षेत्रों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक शून्य-सीमा शुल्क व्यवस्था होना ।

**भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से जून 2020 में संभावित एफटीए के लिए वार्ता की बहाली की घोषणा की। इस वार्ता को प्राथमिकता देते हुए, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने अप्रैल 2022 में एक अंतरिम एफटीए या आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए।**

इसके अलावा, भारत ने यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू और मेर्कोसुर) जैसे क्षेत्रीय गुटों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है।

अब तक भारत ने विभिन्न दायरे वाले 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उन्हें लागू किया। इसने 2000 में श्रीलंका के साथ अपना पहला एफटीए और 2005 में सिंगापुर के साथ पहला सीईपीए लागू किया। भारत ने 1976 से एपीटीए सदस्यों को अधिमान्य व्यापार पहुँच की पेशकश की[2]। भारत द्वारा हस्ताक्षरित और लागू किए गए सभी व्यापार समझौतों की एक विस्तृत सूची अनुलग्नक 1 में दी गई है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से जून 2020 में संभावित एफटीए के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की[3]। इस वार्ता को प्राथमिकता देते हुए, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं ने अप्रैल 2022 में एक अंतरिम एफटीए या आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर किए। जब बातचीत करने वाले देश वास्तविक एफटीए में प्रस्तावित टैरिफ उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान करते हैं तब अंतरिम समझौता दो व्यापारिक साझेदारों के बीच एफटीए का अग्रदूत है। 2011 में शुरू होने से ले कर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में निलंबित करने से पहले नौ दौर की चर्चा की थी[4]। तब से, उनके बीच बहुत कुछ बदल गया है और वे पहले की तुलना में, खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद, करीब आ गए हैं।

2 https://www.bilaterals.org/?-india-

3 चौधरी, राहुल (21 सितंबर, 2021) यह सही समय है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक निर्णायक समझौते पर मुहर लगाने के लिए एफटीए वार्ता फिर से शुरू करें। दक्षिण एशिया मॉनिटर।

4 विदेश मामले व्यापार विभाग, ऑस्ट्रेलिया सरकार।

**2011 में शुरू होने से ले कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2015 में निलंबित होने से पहले नौ दौर की चर्चा हुई थी। तब से, उनके बीच बहुत कुछ बदल गया है और वे पहले की तुलना में, खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद करीब आ गए हैं। क्वाड और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) जैसे मंचों के माध्यम से देश रणनीतिक रूप से करीब आ गए हैं। क्वाड और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) जैसे मंचों के माध्यम से देश रणनीतिक रूप से करीब आ गए हैं।[5]**

हालांकि इन दोनों भागीदारों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन कई वस्तुओं जैसे कि परमाणु आइटम (एच एस 84) रसायन (एच एस 29) और रेलवे और ट्राम (एच एस 87) के अलावा अन्य वाहन उल्लेखनीय रूप से उच्च बने हुए हैं।[6] सेवा व्यापार के मामले में, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया को चुन रहे हैं। शिक्षा भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यात बना हुआ है, जिसका मूल्य 4.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2020 में कुल का लगभग 88 प्रतिशत है। 2020 के अंत में, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की संख्या 115137 थी। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई निवेशक संबंधित बाजारों में अपनी पैठ के अवसरों की तलाश में हैं। द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधि के माध्यम से द्विपक्षीय निवेश संरक्षित किए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार अपनी क्षमता से बहुत कम है और यदि नीतियों को विशेष रूप से उदार टैरिफ दर को अपनाकर अनुकूल रूप से तैयार किया जाता है, तो इसे काफी बढ़ाया जा सकता है। (अहमद, 2011, आलम एट अल. , 2013) प्रस्तावित एफटीए इसी दिशा में एक कदम है। इस पृष्ठभूमि के साथ, वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य व्यापार की उस मात्रा का अनुमान लगाना है जिसे टैरिफ दरों में छूट देकर प्राप्त किया जा सकता है।

5 चौधरी, राहुल (21 सितंबर, 2021) यह सही समय है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक निर्णायक समझौते पर मुहर लगाने के लिए एफटीए वार्ता फिर से शुरू करें। दक्षिण एशिया मॉनिटर. यहां उपलब्ध है: https://www.southasiamonitor.org/spotlight/high-time-in-dia-and-australia-resume-fta-negotiations-seal-conclusive-deall 12.12.21 को एक्सेस किया गया

6 UNCTAD WITS से निकाले गए डेटा के आधार पर।

अध्ययन तीन प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेगा। पहला, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत को कोई लाभ या हानि है और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते से भारत (निर्यातक और आयातक दोनों के रूप में) के लिए संभावित माध्यम और दीर्घकालिक लाभ/हानि क्या होगी? दूसरा, भारत की बातचीत की स्थिति के लिए टैरिफ लाइनों के कवरेज और टैरिफ उदारीकरण के परिमाण की सीमा क्या होनी चाहिए? अंत में, वे कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र/इलाके हैं जिनमें मौजूदा अड़चनें अधिक बाजार एकीकरण को बाधित कर रही हैं? अधिमान्य व्यापार की अवधारणा के दो आयाम हैं: एकपक्षीय, जैसे वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) योजनाएँ, जिससे विकसित देश एकतरफा रूप से विकासशील और कम विकसित देशों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ वरीयताएँ देते हैं और इस तरह आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। अधिमान्य व्यापार का दूसरा रूप पारस्परिक है जहां दो या कई देश एक संविदात्मक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और पारस्परिक रूप से सहमत वस्तुओं और सेवाओं पर एक दूसरे को टैरिफ की अधिमान्य दर की पेशकश करते हैं। यह अध्ययन पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से संबंधित है जिसके तहत देशों के बीच द्विपक्षीय रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जाता है।

शेष अध्ययन निम्नानुसार आयोजित किया जाता है। अध्ययन का अगला भाग रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है। इसके बाद एफटीए के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न एफटीए में भारत की अब तक भागीदारी का वर्णन किया गया है। अध्ययन का चौथा खंड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विश्लेषण करता है। इन दो भागीदारों के बीच प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं के लिए व्यापार की तीव्रता को मापने के लिए व्यापार तीव्रता सूचकांक के निर्माण के बाद इस विश्लेषण का पालन किया जाता है।

छठा खंड गणितीय मॉडल और अध्ययन में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। सातवें खंड में, मॉडल के परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं और अंतिम खंड अध्ययन का समापन करता है।

## भारत ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती साझेदारी

भारत-ऑस्ट्रेलिया सामरिक संबंध लंबे समय से सहयोग की तुलना में अधिक विचलनों द्वारा पहचाने जाते हैं। कुछ समय पहले तक, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में बहुत उतार-चढ़ाव का अनुभव किया गया था। अधिक नियमित राजनयिक जुड़ाव या व्यापार बैठकें नहीं हुई थीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार अपनी पूरी क्षमता से नहीं हो रहा था। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता भी काफी लंबे समय तक ठप रहा। ऐसा लग रहा था कि न तो भारत और न ही ऑस्ट्रेलिया इस रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाने को तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक भागीदारी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोपीय देशों के साथ थी जबकि व्यापार के लिए वह चीन पर बहुत अधिक निर्भर था। प्रारंभिक शीत युद्ध की पृष्ठभूमि के बीच वर्षों के मतभेदों के बाद, दोनों देशों ने 1963 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ वायु सेना अभ्यास ('शिक्षा') में भाग लिया और 1967 में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ताएँ हुईं। 1980 के दशक में विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्रियों (पीएम) इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान और बाद में, 2006 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम जॉन हॉवर्ड और 2017 में मैल्कम टर्नबुल की भारत यात्रा सहित संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए उपयुक्त प्रयास देखे गए, जबकि नवंबर 2014 में भारतीय पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की।

## ऐतिहासिक संदर्भ

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलों में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने 1994 में बड़ी क्षमता वाली एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान की। यह तब हुआ जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और विदेशी भागीदारी के लिए दरवाजा खोल दिया। मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के मेग गुरी ने इसे "मौलिक रूप से अलग रणनीतिक और वाणिज्यिक माहौल के रूप में संदर्भित किया है, जो स्पष्ट रूप से अतीत की तुलना में घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए अधिक अनुकूल है।" 1990 और उसके बाद के दशक में, रिश्ते की क्षमता का पता लगाने और इसे पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाने के लिए कई अकादमिक अध्ययन भी शुरू किए गए (गॉर्डन, 1993; गुरी, 1996; बॉनर, 2001)। एक और सराहनीय पहल 1992 में ऑस्ट्रेलिया-इंडिया काउंसिल की नींव स्थापित करना था। हालाँकि, इन प्रयासों के बावजूद, द्विपक्षीय संबंध अपेक्षा के अनुरूप पुनर्जीवित नहीं हुए"। 1998 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहद कम हो गए जब भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री डाउनर ने भारतीय कदम की कड़ी आलोचना की और परीक्षणों को 'अपमानजनक कृत्य' बताया। ऑस्ट्रेलिया भारत को धमकाने और उस पर कई प्रतिबंध लगाने के लिए लीग ऑफ नेशंस में शामिल हो गया।

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई पहलों में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग ने 1994 में बड़ी क्षमता वाली एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान की। यह तब हुआ जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और विदेशी भागीदारी के लिए दरवाजा खोल दिया।

इसने कुछ वर्षों से चल रहे संबंधों को फिर से जीवंत करने के लगभग सभी द्विपक्षीय प्रयासों को रोक दिया। हालांकि कूटनीतिक जुड़ाव ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए, लेकिन 1990 के दशक की पहली छमाही में उनके बीच व्यापार काफी बढ़ गया, जो 1989-1990 में 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1994-1995 में 881 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2000 और 2009 के बीच व्यापार में प्रति वर्ष 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया का दसवाँ सबसे बड़ा दोतरफा व्यापारिक भागीदार और पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया। इसके अलावा, भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का सत्रहवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत में 22वां सबसे बड़ा निवेशक है।

## रणनीतिक भागीदारी

बढ़ते व्यापार की मात्रा ने दोनों देशों को संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावित किया। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए, सितंबर 2013 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने समान दस्तावेजों की एक श्रृंखला के भाग के रूप में भारत के लिए एक देश रणनीति जारी की जिसमें देशों के आकार, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक संबंधों और क्षेत्र में और विश्व स्तर पर रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण प्राथमिकताओं के रूप में पहचाने गए देशों के साथ संबंधों को विकसित करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई थी। दस्तावेज़ में ऑस्ट्रेलियाई राज्यों और क्षेत्रीय सरकारों, व्यापार प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और सामुदायिक हितधारकों के विचारों को दर्शाया गया है। इस प्रकार, इसने इन विविध श्रेणियों के भागीदारों को जोड़ने के उद्देश्य के कई तरीकों को दर्शाया। आधिकारिक ऑस्ट्रेलियाई बयानों द्वारा प्रबलित यह दस्तावेज़, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक विकास का संकेत देता है।

**बढ़ते व्यापार की मात्रा ने दोनों देशों को संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावित किया। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए, सितंबर 2013 में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने समान दस्तावेजों की एक श्रृंखला के भाग के रूप में भारत के लिए एक देश रणनीति जारी की जिसमें देशों के आकार, ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक संबंधों और क्षेत्र में और विश्व स्तर पर रणनीतिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण प्राथमिकताओं के रूप में पहचाने गए देशों के साथ संबंधों को विकसित करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई थी।**

इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि, ऑस्ट्रेलिया को 2035 तक भारत को अपने शीर्ष तीन निर्यात बाजारों में ऊपर उठाने, भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाहरी निवेश के लिए एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बनाने, भारत को ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी के आंतरिक दायरे में लाने तथा लोगों से लोगों के बीच संबंधों को किसी भी एशिया देश जितने करीबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह रिपोर्ट क्षेत्रवार मूल्यांकन करती है और सहयोग के लिए 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करती है। रिपोर्ट ने सहयोग बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला की सिफारिश की। बाद में 2018 में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की आर्थिक रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से एक और अध्ययन शुरू किया। भारत ने पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) के रूप में सेवानिवृत्त हुए, के नेतृत्व में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा (क्लिनवेल्ड पीट मारविक गोएर्डेलर) केपीएमजी के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग के मौजूदा और संभावित क्षेत्रों की पहचान की। लेखक फार्मा, खनन आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों का सुझाव देता है जिसमें भारत अपनी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग कर सकता है। रिपोर्ट आगे "भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा संवाद" के पुनरुद्धार की सिफारिश करती है और विशेष रूप से सौर पैनलों, पवन चक्कियों, हाइड्रोजन ईंधन आदि पर ध्यान देने के साथ - नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

बदलती वैश्विक भू-राजनीति के साथ, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखना शुरू कर दिया।

**बदलती वैश्विक भू-राजनीति के साथ, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में एक दूसरे को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखना शुरू कर दिया। इससे 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा सहित एक 'रणनीतिक साझेदारी' के लिए द्विपक्षीय संबंधों का उन्नयन हुआ।**

इससे 2009 में सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा सहित एक 'रणनीतिक साझेदारी' के लिए द्विपक्षीय संबंधों का उन्नयन हुआ। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। द्विपक्षीय तंत्र में उच्च स्तरीय यात्राएं, प्रधानमंत्रियों की वार्षिक बैठकें, विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता, संयुक्त व्यापार और वाणिज्य मंत्रिस्तरीय आयोग, भारत-ऑस्ट्रेलिया '2 + 2' विदेश सचिवों और रक्षा सचिवों की वार्ता, रक्षा नीति वार्ता, ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद, रक्षा सेवा कर्मचारी वार्ता, ऊर्जा सुरक्षा संवाद", विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) आदि शामिल हैं।।

## चीन घटक

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती निकटता के लिए चीन एक महत्वपूर्ण कारक है। "चीन के उदय और आचरण का प्रभाव के ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए गहरे निहितार्थ हैं। लद्दाख में झड़प के बाद, जिसमें बीस भारतीय सैनिक और अज्ञात संख्या में चीनी सैनिक मारे गए, भारत और चीन के बीच संबंध तेजी से बिगड़ने लगे।

**भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती निकटता के लिए चीन एक महत्वपूर्ण कारक है। "चीन के उदय और आचरण के प्रभाव के ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए गहरे निहितार्थ हैं।**

चीन के आचरण पर आपत्ति जताते हुए भी भारत सार्वजनिक रूप से चीन का नाम लेने से हमेशा हिचकता रहा है। ऐसा न केवल व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ है बल्कि तब भी हुआ है जब चीन ने सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाया है। न केवल भारत चीनी कार्रवाइयों की खुले तौर पर आलोचना नहीं करता है, बल्कि यह लगातार चीन का नाम लेकर उसकी निंदा करने से बचता है। उदाहरण के लिए, भारत ने दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता के मुद्दे का बार-बार समर्थन किया है और मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय के फैसले का भी समर्थन किया है, दोनों स्पष्ट रूप से चीन को लक्षित हैं।

भारत और चीन परंपरागत रूप से प्रतिस्पर्धी रहे हैं। उनमें से पहला लम्बे समय से चल रहा भारत-चीन सीमा विवाद है, जिसके परिणामस्वरूप 1962 का सीमा युद्ध और हाल ही में 2013, 2014, 2017 और 2020 में सैन्य गतिरोध हुआ। दूसरा दक्षिण एशिया और हिंद महासागर सहित भारत के पड़ोस में चीनी प्रभुत्व के बारे में लगातार चिंताएं हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की आड़ में, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और नेपाल में अधिक चीनी आर्थिक संसाधनों के निवेश के साथ-साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य संसाधनों के निवेश ने भारतीय बेचैनी को हवा दी है, ऐसा ही हिंद महासागर में एक स्थायी चीनी सैन्य उपस्थिति की बढौतरी के कारण हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंधों में मजबूत व्यापार और आर्थिक संबंध होने के बावजूद मतभेद उत्पन्न हुए। चीन ऑस्ट्रेलियाई निर्यात के लिए सबसे बड़ा गंतव्य स्थान रहा है। चीन के साथ फलते-फूलते व्यापारिक संबंधों ने ऑस्ट्रेलियाई समृद्धि को अत्यधिक प्रेरित किया है। ऑस्ट्रेलिया में चीनी डायस्पोरा में वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में चीनी निवेश को बढ़ाने में काफी हद तक सहायक रही है।

इन सभी विकासों के साथ विशेष रूप से 5जी दूरसंचार प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में चीनी निवेश से चिंताएँ बढ़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में चीन की कथित संलग्नता और दक्षिण चीन सागर में उसके बढ़ते नौसैनिक अभ्यास ने ऑस्ट्रेलियाई नीति निर्माताओं को चिंतित कर दिया है। इनके प्रत्युत्तर में ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी स्रोतों से राजनीतिक चंदे से संबंधित अपनी नीति को कड़ा किया और अपनी सुरक्षा रणनीति में संशोधन किया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण प्रशांत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान, भारत और अमेरिका में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ संरेखित करने के लिए एक प्रमुख विदेश नीति को आगे बढ़ाया।

## सांस्कृतिक संबंध

सहयोग के विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने लोगों से लोगों के संपर्क के माध्यम से मजबूत और स्थायी संबंध भी बना रहे हैं। दोनों सरकारें सांस्कृतिक कूटनीति को द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण बनाने में विश्वास करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख की जनसंख्या आकार के साथ भारतीय समुदायों की एक उल्लेखनीय संख्या (भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवासी दोनों शामिल हैं) और उनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रवासी हैं । हिंदू धर्म हमारा सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और पंजाबी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है । भारत ऑस्ट्रेलिया में कुशल अप्रवासियों के शीर्ष स्रोतों में से एक है।

**ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न राज्यों में लगभग सात लाख की जनसंख्या आकार के साथ भारतीय समुदायों की एक उल्लेखनीय संख्या (भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवासी दोनों शामिल हैं) और उनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है।**

**लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष बारी-बारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया में "ऑस्ट्रेलिया भारत युवा संवाद (एआईवाईडी)" का आयोजन करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पूर्व-प्रतिष्ठित ट्रैक-दो युवा नेताओं का संवाद है। एआईवाईडी एक वार्षिक सम्मेलन में प्रत्येक देश के 15 सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली युवा दिमागों की मेजबानी करता है।**

वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 115137 छात्रों के साथ भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि जारी है। इंग्लैंड के बाद, भारत 2020 में ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। भारतीय त्यौहार, विशेष रूप से दीपावली, होली और दुर्गा पूजा ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में समुदाय के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष बारी-बारी से भारत और ऑस्ट्रेलिया में "ऑस्ट्रेलिया भारत युवा संवाद (एआईवाईडी)" का आयोजन करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पूर्व-प्रतिष्ठित ट्रैक-दो युवा नेताओं का संवाद है। एआईवाईडी एक वार्षिक सम्मेलन में प्रत्येक देश के 15 सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली युवा दिमागों की मेजबानी करता है। एआईवाईडी उभरते भविष्य के नेताओं के बीच महान विचारों के संग्रह को एक साथ लाने में मदद करता है ताकि गंभीर रूप से रचनात्मक रूप से सोचा जा सके कि कैसे ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध अपने स्वयं के काम और प्रयासों के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं।

## आईओआर में रक्षा और समुद्री सहयोग

हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए प्रमुख भू-रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। दोनों देशों की नौसेनाएँ विदेश नीति की प्राथमिकता के रूप में जलडमरूमध्य की सुरक्षा और संरक्षा के रखरखाव में सक्रिय रूप से लगी हुई है। विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलों के माध्यम

से, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इस क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2020 में, भारत जिबूती आचार संहिता (डीसीओसी) (पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती के दमन से संबंधित आचार संहिता) में शामिल हो गया, जो समुद्री डकैती के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। जबकि इसकी सदस्यता में आईओआर के पश्चिमी भाग में तटीय देश शामिल हैं, भारत यूएस, यूके, जापान और नॉर्वे के साथ डीसीओसी के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। निस्संदेह, पर्यवेक्षकों की सूची में ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना डीसीओसी के समुद्री डकैती विरोध के एजेंडे के दायरे को आईओआर के सबसे पूर्वी छोर तक विस्तारित करने में भी उपयोगी साबित होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए समुद्री सहयोग पर सबसे बेशकीमती बहुपक्षीय पहलों में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) और हिंद महासागर क्षेत्र संघ (आईओआरए) शामिल हैं। जबकि 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित आईओएनएस, अपने आईओआर समकक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा के मुद्दों के आसपास संवाद बनाने के लिए कार्य करता है, आईओआरए, जिसे 1997 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से परिकल्पित किया गया था, समग्र रूप से आईओआर के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श के लिए एक अंतर-सरकारी मंच (मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में) के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सबसे प्रमुख पहल क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या **'क्वाड'** है, जो चार हिन्द-प्रशांत शक्तियों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान) का एक समूह है जो उनके स्वयं के लाभ के लिए "एशियन आर्क ऑफ़ डेमोक्रेसी" का निर्माण करता है। **'क्वाड'** का नए सिरे से फोकस न केवल क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का प्रतिकार करना है, बल्कि उच्च समुद्र से आतंकवाद और समुद्री डकैती जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरों को खत्म करना भी है। द्विपक्षीय स्तर पर, भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देशों की नौसेनाओं और तट रक्षकों के लिए सहयोग और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने का प्रयास करते हुए, समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए एक नौसैनिक अभ्यास **ऑसइंडेक्स** में संलग्न हैं।

**ऑसइंडेक्स** के चौथे संस्करण में, जो सितंबर 2021 में संपन्न हुआ, दोनों देशों के युद्धपोतों, गश्ती विमानों, पनडुब्बियों, सामरिक लड़ाकू विमानों और हेलीकाप्टरों के बीच संयुक्त पुनःपूर्ति, प्रतिक्रिया और अन्य अभ्यास किए गए। मालाबार 2021, इस साल अगस्त में आयोजित चार **'क्वाड'** देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, चार देशों की समुद्री सेनाओं के बीच नौसेना-से-नौसेना युद्ध प्रशिक्षण, गनरी इवेंट्स और क्रॉस-डेक उड़ान संचालन भी हुए।

अधिक सहयोग के लिए भी उत्साह है, जैसे कि "ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान और ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय संवाद। ये प्रतिनिधित्व करते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई रक्षा अधिकारी ने क्षेत्र की "घनी वास्तुकला" के रूप में क्या वर्णित किया है। मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो के बीच 2018 के शिखर सम्मेलन के बाद भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक संबंधों को अपने आप में एक प्रोत्साहन मिला। भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान त्रिपक्षीय जुड़ाव एक पूरक संबंध के विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सितंबर 2021 में अपनी पहली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और महिला मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन एमपी ने 10-11 सितंबर को भारत के अपने समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की। इस बातचीत के केंद्र में, जो जून 2020 में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में लिए गए एक निर्णय से उत्पन्न हुआ, एक खुले, मुक्त, समृद्ध और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के उनके साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का उद्देश्य था। उन्होंने गति बनाए रखने के लिए इस प्रारूप में हर दो साल में कम से कम एक बार मिलने का फैसला किया है।

इस संवाद के दौरान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपनी रक्षा सेवाओं के बीच परिचालन अनुकूलता को सशक्त बनाने के लिए भविष्य के तावीज़ कृपाण अभ्यास, में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उम्मीद की जाती है, यह अभ्यास अंतरसंचालानीयता बढ़ाएगा, जबकि दोनों पक्ष रसद सहयोग में लंबी अवधि के पारस्परिक व्यवस्थाओं का पता लगाएंगे।

## ऊर्जा सहयोग

ऊर्जा किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल होती है क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था ऊर्जा संसाधनों से चलती है और भारत इस संबंध में कोई अपवाद नहीं है। "यह भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में एक प्रमुख स्थान रखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजादी के बाद से भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबा सफर तय किया है। खपत के उच्च स्तर के साथ, औद्योगिक और घरेलू दोनों में, एक ऐसे चरण का नेतृत्व किया है जहां ऊर्जा की आपूर्ति माँग से कम हो जाती है। पिछले कुछ समय से सरकार का मुख्य ध्यान अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण पर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास जैसी ऊर्जा-गहन परियोजनाएं सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएँ हैं। और यहीं पर, इसके प्रचुर ऊर्जा संसाधनों को देखते हुए भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का महत्व निहित है। दोनों देश भू-तापीय और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही अन्य बातों के साथ-साथ स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के तरीके और साधन खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत नियमित रूप से संयुक्त वार्ता करते हैं। हाल ही में आयोजित द ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एनर्जी डायलॉग, ऊर्जा और संसाधनों पर द्विपक्षीय जुड़ाव पर चर्चा करने का प्राथमिक मंच है। यह "ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी मंत्री और संबंधित भारतीय समकक्ष के बीच एक मंत्रिस्तरीय संवाद है।

संवाद वार्षिक रूप से  भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ होता है और इसमें दोनों मंत्रियों द्वारा भाग लिया जाता है।  ऊर्जा संवाद का समर्थन करने के लिए 4 कार्य समूह स्थापित किए जा रहे हैं: 1. नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड 2. बिजली और ऊर्जा दक्षता 3. कोयला और खदानें 4. तेल और गैस। कार्य समूहों में भाग लेने वालों में सरकार के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और उद्योग शामिल हैं। फरवरी 2022 में, भारत ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय, ऊर्जा दक्षता, भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), महत्वपूर्ण खनिजों, खनन आदि पर ध्यान देने के साथ अपने अपने  देशों में चल रही ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए अपने चौथे ऊर्जा संवाद संपन्न किया। विकासशील देशों के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत द्वारा जलवायु वित्त की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

## विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में औपचारिक सहयोग 1986 में दोनों सरकारों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग, नवाचार और विज्ञान विभाग, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 2003 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1996 में हस्ताक्षरित मूल समझौता ज्ञापन के स्थान पर था।

**ऊर्जा संवाद का समर्थन करने के लिए 4 कार्य समूह स्थापित किए जा रहे हैं: 1. नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड 2. बिजली और ऊर्जा दक्षता 3. कोयला और खदानें 4. तेल और गैस। कार्य समूहों में भाग लेने वालों में सरकार के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और उद्योग शामिल हैं।**

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो गतिविधियों के संयुक्त वित्त पोषण का समर्थन करता है। 2011 में, इस समझौता ज्ञापन को 2016 तक पाँच साल के लिए और बढ़ा दिया गया था।

भारत तेजी से एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं का एक प्रमुख स्रोत है। अनुमान है कि उन क्षेत्रों की भारतीय कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया सहित 80 देशों में 1,000 से अधिक वैश्विक वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट शहरों और जीवंत साइबर सुरक्षा और स्टार्ट-अप क्षेत्रों में नए निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को हमारी डिजिटल दुनिया का लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में तुलनात्मक वैश्विक ताकत है। वर्तमान सरकार ने रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निरंतर निवेश के लिए आकाँक्षा दिखाना जारी रखा है। सरकार भर में, सार्वजनिक सेवा तेजी से प्रौद्योगिकी नीति विशेषज्ञता में निवेश कर रही है, और अभी भी व्यवस्थित होने के दौरान, उस क्षेत्र में नीति निर्माण धीरे-धीरे अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक होता जा रहा है।

कई डोमेन (अर्थशास्त्र, मौसम विज्ञान, नेविगेशन और सेना सहित) में अंतरिक्ष की बढ़ती प्रासंगिकता अवसरों और चुनौतियों पर आगे के सहयोग के लिए तैयार स्थितियाँ प्रदान करती है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत अलग हैं (भारत में ये लंबे समय से और स्थापित है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अभी शुरुआत कर रहा है), तथापि अभी भी सफल सहयोग के लिए रास्ते उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रस्तावों के बीच अंतराल को पाटने के अपने प्रयासों के संयोजन में दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो एक सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ तरीके से अंतरिक्ष के उपयोग को सुनिश्चित करना चाहते हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य मध्य शक्तियों और समान विचारधारा वाली सरकारों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान तैयार कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त साइबर नीति संवाद आयोजित करते हैं । संवाद वर्तमान और उभरते साइबर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें उभरती हुई आईसीटी प्रौद्योगिकियाँ, साइबर सुरक्षा नीति और कानून के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण, संयुक्त राष्ट्र के सरकारी विशेषज्ञों और ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, और साइबर-अपराध को संबोधित करने के लिए सहयोग पर हमारे अपने-अपने विचारों सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल हैं । दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता के प्रति अपनी निरंतर चिंता का उल्लेख किया, जो संबंधित देशों की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता रखती हैं । भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया-भारत फ्रेमवर्क व्यवस्था के माध्यम से जून 2020 में सीईपीए के तहत साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय साइबर सुरक्षा को बढ़ाया ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक मुद्दों पर संयुक्त अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, 2006 में "ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष (एआईएसआरएफ) स्थापित किया गया था । ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष (एआईएसआरएफ) संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और भारत की सरकारों द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित है। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं को अति-आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यशालाओं में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ भाग लेने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। उच्च कार्य-प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई और शुरुआती और

मध्य-कैरियर शोधकर्ता भारत की यात्रा के लिए फंडिंग का उपयोग कर सकते हैं और प्रमुख भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों में प्रमुख शोधकर्ताओं के साथ काम कर सकते हैं "। भारत सरकार ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों में समय बिताने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं का भी समर्थन करती है। ये पारस्परिक फैलोशिप हमारे राष्ट्रों के बीच दीर्घकालिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं।

2006 में इसकी स्थापना के बाद से, एआईएसआरएफ ने ऑस्ट्रेलिया और भारत की प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों में 230 से अधिक संयुक्त परियोजनाओं, कार्यशालाओं और फैलोशिप का समर्थन किया है, जिसमें दोनों देशों के लगभग 100 शीर्ष विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं । सितंबर 2014 में घोषित एआईएसआरएफ के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर का विस्तार हमारे दोनों देशों के बीच इस फंड की सफलता और महत्व और विज्ञान और उद्योग को एक साथ आगे बढ़ाने की क्षमता के लिए एक प्रमाण है। इस विस्तार का मतलब यह होगा कि एआईएसआरएफ द्विपक्षीय अनुसंधान के लिए समर्पित ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फंड बना हुआ है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कुल प्रतिबद्धता को 84 मिलियन डॉलर तक बढ़ाता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया, जिसने सहयोग के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें शिक्षा नीति में सहयोगी अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में क्षमता निर्माण और उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा शामिल हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में, भारत (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) और ऑस्ट्रेलिया (शिक्षा, कौशल और रोजगार विभाग) के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक 26 नवंबर 2020 को आभासी रूप में आयोजित की गई थी।

## भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 1.3 अरब लोगों का बाजार है। इसकी युवा आबादी, विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था और विकास प्रक्षेप-पथ  शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, संसाधन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचे, विज्ञान और नवाचार, और खेल सहित ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। अगले 20 वर्षों में, बढ़ते हुए भारत को कृषि, शिक्षा एवं  कौशल प्रशिक्षण, और स्वास्थ्य सेवा सहित ऑस्ट्रेलिया की कई वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होगी।

हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई पूरकताओं से प्रेरित है। वस्तुओं और सेवाओं में दो-तरफा व्यापार 2007 में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही व्यापार और आर्थिक रूपरेखा (टीईएफ) समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

**हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई पूरकताओं से प्रेरित है। वस्तुओं और सेवाओं में दो-तरफा व्यापार 2007 में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही व्यापार और आर्थिक रूपरेखा (टीईएफ) समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।**

टीईएफ में केंद्रित प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र /कपड़े, जूते और कृषि के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा ऊर्जा और खनन, बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तपोषण, आईसीटी, शिक्षा, पर्यटन, फिल्म और मनोरंजन, जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं। टीईएफ के तहत की गई पहलें इन क्षेत्रों के तहत वाणिज्यिक अवसरों की पहचान करने में मदद करेगी।

नीचे दिया गया चित्र 1, 2003 से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्यात और आयात को दिखाता है। डेटा दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 2003 से 2011 तक लगातार बढ़ा; जबकि 2011 के बाद के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव का रुझान देखा गया है। संदर्भ अवधि के दौरान, भारतीय आयात 2017 में अपने चरम पर पहुँच गया और 2020 में तेजी से गिर गया। इस कमी का प्राथमिक कारण कोविड-19 महामारी का प्रकोप है। संदर्भ अवधि के दौरान 2017 में भारतीय आयात में बेतहाशा वृद्धि के साथ यह महज 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 17.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस समय अवधि के दौरान भारतीय आयात में 700 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

ऑस्ट्रेलिया को अपने निर्यात में भारत ने लगभग एक निरंतर प्रवृत्ति बनाए रखी; हालाँकि, यह अध्ययन की संदर्भ अवधि में समय के साथ बढ़ता गया। लेकिन निर्यात और आयात के बीच एक व्यापक अंतर बना हुआ है। सभी वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा रहा है। 2020-21 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की भारत के कुल निर्यात में 1.39 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि इसके सकल आयात में 2.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची अनुबंध 2 और 3 में दी गई है।

**निर्यात और आयात के बीच एक व्यापक अंतर बना हुआ है। सभी वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटा रहा है। 2020-21 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की भारत के कुल निर्यात में 1.39 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि इसके सकल आयात में 2.9 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।**

हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में एक स्पष्ट व्यापार असंतुलन है लेकिन जब तक कि भारत का समग्र व्यापार संतुलन सकारात्मक है यह शायद ही कोई समस्या पैदा करेगा। दीर्घावधि में इसके ठीक होने की भी संभावना है क्योंकि भारत अधिक परिष्कृत निर्माणों और सेवाओं की एक बड़ी श्रृंखला विकसित करता है। हालाँकि, यह एक अल्पकालिक अड़चन साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत आउटसोर्सिंग से जुड़े मुद्दों को समझाने और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए द्विपक्षीय और विश्व व्यापार संगठन और जी20 जैसे प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम करने पर विचार कर सकते हैं।

रेखाचित्र 1: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार (बिलियन अमरीकी डॉलर में)

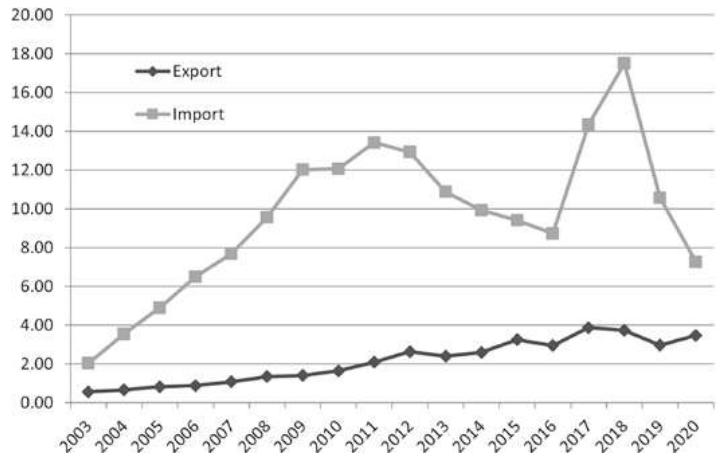


स्रोत: यू एन कॉमट्रेड डेटा के आधार पर लेखक की गणना।

**तालिका 1**

**भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार (बिलियन अमरीकी डॉलर में)**

| वर्ष | निर्यात | आयात |
|---|---|---|
| 2003 | 0.56 | 2.04 |
| 2004 | 0.66 | 3.55 |
| 2005 | 0.83 | 4.90 |
| 2006 | 0.89 | 6.50 |
| 2007 | 1.08 | 7.68 |
| 2008 | 1.35 | 9.57 |
| 2009 | 1.41 | 12.02 |
| 2010 | 1.65 | 12.06 |
| 2011 | 2.10 | 13.42 |
| 2012 | 2.63 | 12.93 |
| 2013 | 2.40 | 10.87 |
| 2014 | 2.59 | 9.93 |
| 2015 | 3.25 | 9.41 |
| 2016 | 2.95 | 8.73 |
| 2017 | 3.88 | 14.35 |
| 2018 | 3.73 | 17.51 |
| 2019 | 2.97 | 10.57 |
| 2020 | 3.47 | 7.26 |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड

**तालिका 2**

2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करने वाली भारत की शीर्ष 10 वस्तुएँ (मिलियन अमरीकी डॉलर)

| क्रम सं. | एचएस कोड | उत्पादन | निर्यात मूल्य |
|---|---|---|---|
| **1** | **27** | खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पाद | **353.4** |
| **2** | **71** | **प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती, कीमती पत्थर** | **268.9** |
| **3** | **30** | **दवा उत्पाद।** | **251.8** |
| **4** | **86** | **रेलवे/ट्रामवे, रोलिंग-स्टॉक और** | **169.5** |
| **5** | **84** | **परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एंड एम** | **157.6** |
| **6** | **73** | **लोहे या स्टील की सामग्री** | **139.9** |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 85 | इलेक्ट्रिकल मशीन उसके उपकरण पुर्जे | 137.2 |
| 8 | 62 | परिधान और कपड़ों की पहुंच की कला, और | 128.8 |
| 9 | 63 | अन्य निर्मित कपड़ा वस्तुएँ; सेट | 128 |
| 10 | 61 | परिधान की कला और कपड़ों की पहुंच | 88.9 |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड

**तालिका 3**

2019 के दौरान ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली भारत की शीर्ष 10 वस्तुएँ (मिलियन अमरीकी डॉलर)

| एचएस कोड | उत्पादन | निर्यात मूल्य |
|---|---|---|
| 27 | खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पाद | 8224.2 |
| 71 | प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती, कीमती पत्थर | 529.9 |
| 28 | इनऑर्गनिक रसायन; प्रीसीएमटीएल अवयव , | 403 |
| 26 | अयस्क, लावा और राख | 258.2 |
| 76 | एल्यूमीनियम और उसकी वस्तुएँ | 137.7 |
| 51 | ऊन, महीन/मोटे पशु बाल, घोड़े | 125.9 |
| 72 | लोहा और इस्पात। | 99.7 |
| 32 | टैनिंग/रंगाई अर्क ; टैनिन और | 84.3 |
| 8 | खाद्य फल और मेवे; साइट्रस का छिलका | 70.6 |
| 84 | परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मची एंड एम | 61.1 |
| 90 | ऑप्टिकल, फोटो, सिने, मीस, चेकइन | 56.2 |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड

**तालिका 4**

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वस्तुओं द्वारा भरा जाने वाले शुल्क (बाइंडिंग / भारित औसत)

| एचएस कोड | उत्पादन | टैरिफ (%) |
|---|---|---|
| 27 | खनिज ईंधन, उसके तेल | 1.61 |
| 71 | प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती, कीमती पत्थर | 9.54 |
| 30 | दवा उत्पाद। | लागू नहीं |
| 86 | रेलवे/ट्रामवे, रोलिंग-स्टॉक | 15.13 |
| 84 | परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीन | 8.77 |
| 73 | लोहे या स्टील की वस्तुएँ | लागू नहीं |
| 85 | इलेक्ट्रिकल मशीन उपकरण उसके पुर्जे | 8.38 |

स्रोत: विट्स, ट्रेन्स

| एचएस कोड | उत्पादन | टैरिफ (%) |
|---|---|---|
| 62 | परिधान और कपड़ों की पहुँच की कला, एनईसी | 41.46 |
| 63 | अन्य निर्मित कपड़ा वस्तुएँ | 23.86 |
| 61 | परिधान और कपड़ों की पहुँच की कला | 42.06 |
| 87 | रेलवे/ट्रामवे, रोलिंग-स्टॉक पर वाहन | 10.42 |
| 42 | चमड़े की वस्तुएं; काठी / हार्नेस | 15.74 |

स्रोत: विट्स, ट्रेन्स

**तालिका 5**

**भारत में ऑस्ट्रेलियाई वस्तुओं द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क (बाध्यकारी / भारित औसत)**

| एचएस कोड | उत्पादन | टैरिफ (%) |
|---|---|---|
| 27 | खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पाद | 29.17 |
| 71 | प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती, कीमती पत्थर | 40 |
| 28 | अकार्बनिक रसायन; कीमती धातु के अवयव | 40 |
| 26 | अयस्क, लावा और राख। | 32.5 |
| 76 | एल्यूमीनियम और उसकी वस्तुएँ | लागू नहीं |
| 51 | ऊन, महीन/मोटे पशु बाल, घोड़े | 43.33 |
| 72 | लोहा और इस्पात। | 40 |
| 32 | टेनिंग /रंगाई अर्क ; टैनिन | 40 |
| 8 | खाद्य फल और मेवे; साइट्रस का छिलका | 85 |
| 84 | परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीन | 29.2 |
| 90 | ऑप्टिकल, फोटो, सिने, मीस, चेकइन | 31.33 |
| 31 | उर्वरक। | 5 |
| 7 | खाद्य सब्जियां और कुछ जड़ें | 91.88 |

स्रोत: विट्स, ट्रेन्स

तालिका 2 और 3 ऑस्ट्रेलिया से भारत के शीर्ष निर्यात और आयात वस्तुओं को दिखाती हैं। महत्वपूर्ण रूप से, निर्यात और आयात दोनों के मामले में शीर्ष 10 मदें भारत के ऑस्ट्रेलिया से कुल व्यापार में 60 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। खनिज ईंधन, तेल (एचएस 27), प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती (एचएस 71) फार्मास्युटिकल उत्पाद (एचएस 30), रेलवे ट्राम और लोकोमोटिव इंजन (एचएस 86) जैसे उत्पाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में से हैं।

अकार्बनिक रसायन (एचएस 28), अयस्क, लावा और राख (27), खनिज ईंधन, तेल (एचएस27), प्राकृतिक/सुसंस्कृत मोती (एचएस 71) ऑस्ट्रेलिया से भारत की प्राथमिक आयात वस्तुओं में से हैं। तालिका 4 और 5 क्रमशः ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात और भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात द्वारा अदा किए जाने वाले टैरिफ को दिखाते हैं। आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय शुल्क ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत अधिक हैं। उच्च टैरिफ के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से भारतीय आयात समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि टैरिफ व्यापार को कम करने या बढ़ाने के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हैं। भारत के पास अपनी टैरिफ दर को कम करने और ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर तरजीही शुल्कों की पेशकश करने की बहुत गुंजाइश है। आयात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में भारत की उच्चतम टैरिफ दर 90 प्रतिशत से अधिक है जो खाद्य सब्जियों (एचएस 07) पर लागू है जबकि न्यूनतम दर 5 प्रतिशत है जो उर्वरकों (एचएस 31) पर लगाई जाती है। उच्चतम ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ दर 42.06 है जो परिधान कला एवं कपडा पहुँच (एचएस 61) पर लागू होती है और न्यूनतम टैरिफ दर 1.61 प्रतिशत खनिज ईंधन (एचएस 27) पर लगाई जाती है।

## व्यापार गहनता सूचकांक (टीआईआई) विश्लेषण

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार की सापेक्ष गहनता को समझने के लिए, हमने व्यापार गहनता सूचकांक (टीआईआई) को मापा। किसी देश के लिए टीआईआई विश्व आयात की तुलना में किसी दिए गए देश से आयात की सापेक्ष स्थिति को सारांशित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी दिए गए उत्पाद के लिए विश्व आयात के मुकाबले भारतीय आयात का सापेक्ष महत्व बढ़ रहा है, तो वह बाजार भारत के लिए निर्यात संभावित बाजार के रूप में उभर रहा है। इसके विपरीत यदि किसी उत्पाद के लिए विश्व आयात की तुलना में भारतीय आयात का सापेक्ष महत्व कम हो रहा है, तो उस बाजार को गिरावट वाला बाजार कहा जाता है। टीआईआई की गणना निम्नानुसार की जाती है:

$$\text{टीआईजे} = \frac{X_{ij} / X_{it}}{X_{wj} / X_{wt}}$$

कहाँ ,

$Xij$ भारत द्वारा देश $j$ को एक विशेष वस्तु का निर्यात है,

$Xii$ भारत का कुल निर्यात है,

xwj देश j के लिए एक विशेष वस्तु का विश्व निर्यात है और

$Xwí$ कुल विश्व निर्यात है।

एक से अधिक मूल्य के साथ व्यापार गहनता का सूचकांक उच्च द्विपक्षीय व्यापार का संकेत है, जिसकी विश्व व्यापार में देशों की हिस्सेदारी के आधार पर अपेक्षा की जा सकती है। समय के साथ सूचकांक के मूल्य में परिवर्तन से पता चलता है कि क्या कोई दो देश/समूह एक दूसरे के साथ व्यापार करने की प्रवृत्ति में वृद्धि या कमी का अनुभव कर रहे हैं। सूचकांक का बढ़ता मूल्य आगे एकीकरण के लिए बढ़ी हुई संभावनाओं का संकेत है जबकि घटता मूल्य कम संभावनाओं का संकेत देगा। टीआईआई मान, तालिका 6 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 6

**भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार की गहनता**

| वर्ष | टीआईआई |
|---|---|
| 2009 | 0.5 |
| 2010 | 0.5 |
| 2011 | 0.5 |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड डेटा पर आधारित लेखक की गणना।

| वर्ष | टीआईआई |
|---|---|
| **2012** | **0.6** |
| **2013** | **0.5** |
| **2014** | **0.6** |
| **2015** | **0.9** |
| **2016** | **0.9** |
| **2017** | **1.0** |
| **2018** | **0.9** |
| **2019** | **0.7** |
| **2020** | **1.0** |

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड डेटा पर आधारित लेखक की गणना।

**टीआईआई** मान बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय व्यापार 2020 के अलावा कभी भी 1 से ऊपर नहीं रहा है। हालाँकि, वर्ष 2020 को कोविड-19 के कारण व्यापार में व्यवधान के कारण किसी भी बदलाव का संकेत नहीं माना जा सकता है। टीआईआई मूल्यों से पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार विश्व व्यापार में उनकी सापेक्ष स्थिति को देखते हुए इसकी क्षमता से बहुत कम है। यह भविष्य में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्च व्यापार की संभावना को दर्शाता है।

इस व्यापार की संभावनाओं को विस्तार से समझने के लिए, हमने दुनिया से ऑस्ट्रेलिया की 10 शीर्ष आयात वस्तुओं के लिए टीआईआई की गणना की। इसका मतलब है कि अगर उन वस्तुओं के लिए टीआईआई भी कम है, तो यह भारतीय निर्यात के लिए और अधिक सम्भावना खोलेगा। मान अपेक्षित परिणाम दिखाते हैं। भारत के 5 वस्तुओं के लिए उच्च टीआईआई मूल्य हैं जबकि दो वस्तुओं के लिए इसके टीआईआई मूल्य कम हैं। इसके अलावा, दो वस्तुओं का निर्यात नियमित नहीं है। यह भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने व्यापार को तेज करने की एक बड़ी गुंजाइश देता है। (तालिका 7 देखें)

**टीआईआई मूल्यों से पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार विश्व व्यापार में उनकी सापेक्ष स्थिति को देखते हुए इसकी क्षमता से बहुत कम है।**

**तालिका 7**

2019 **में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष आयातक वस्तुओं के लिए भारत का टीआईआई**

| एचएस कोड | उत्पाद विवरण | टीआईआई मूल्य |
|---|---|---|
| **271019** | **लाइट पेट्रोलियम डिस्टिलेट एनईएस।** | **93.1** |
| **270900** | **पेट्रोलियम तेल, बिटुमिनस खनिजों से तेल, कच्चा तेल** | **0.0** |
| **870323** | **मोटर कार** | **0.0** |
| **870421** | **मोटर कार** | **1.3** |
| **710812** | **कच्चे रूप में सोना गैर-मौद्रिक** | **0.0** |
| **300490** | **दवाएँ एनईएस।** | **286.1** |
| **851712** | **तारहित हैंडसेट के साथ टेलीफोन सेट** | **0.6** |
| **847130** | **डाटा प्रोसेसिंग मशीनें** | **0.3** |
| **851762** | **संचार मशीन** | **1.9** |
| **271012** | **मोटर वाहनों के लिए पेट्रोलियम स्पिरिट** | **222.4** |

स्रोत: डब्ल्यूआईटीएस डेटा के आधार पर लेखक की गणना

## अध्ययन की पद्धति[7]

टैरिफ उन्मूलन के संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, अध्ययन **'स्मार्ट'** (बाजार विश्लेषण और व्यापार पर प्रतिबंध के लिए सॉफ्टवेयर) मॉडल लागू करता है। **'स्मार्ट'** विश्व एकीकृत व्यापार समाधान (डब्ल्यूआईटीएस) के तहत उपलब्ध विश्व बैंक द्वारा विकसित एक आंशिक संतुलन मॉडलिंग उपकरण है। विश्लेषण एचएस 6 अंकों के स्तर पर किया जाएगा।

**'स्मार्ट मॉडल'** व्यापार नीति में बदलाव होने पर किसी विशेष बाजार में आयात में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है। **'स्मार्ट'** में बाजार का माँग पक्ष अरमिंग्टन की धारणा पर आधारित है कि वस्तुओं को उनके मूल देश द्वारा विभेदित किया जाता है। इस धारणा का तात्पर्य है कि, किसी विशेष

इस अध्ययन में उपयोग किए गए स्मार्ट मॉडल के बारे में 'विवरण'
वीएडीबी प्रकाशन, 'मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव मूल्यांकन के लिए पद्धति' से अपनाया गया है।'

वस्तु के लिए, एक देश से आयात दूसरे देश से आयात के लिए एक अपूर्ण विकल्प है। इस प्रकार, भले ही एक एफटीए में अधिमान्य व्यापार उदारीकरण शामिल है, आयात माँग पूरी तरह से एफटीए के भीतर से एक स्रोत में स्थानांतरित नहीं होती है। **'स्मार्ट मॉडल'** यह भी मानता है कि उपभोक्ताओं की माँग को दो चरणों वाली इष्टतम प्रक्रिया में तय किया जाता है जिसमें कमोडिटी और राष्ट्रीय विविधता द्वारा अपने खर्च को आवंटित करना शामिल होता है। पहले चरण में, उपभोक्ता तय करते हैं कि दी गई वस्तु पर कितना खर्च करना है। दूसरे चरण में, प्रत्येक किस्म के सापेक्ष मूल्य के आधार पर, इस वस्तु के लिए खर्च का चुना हुआ स्तर विभिन्न राष्ट्रीय किस्मों के बीच आवंटित किया जाता है। सापेक्ष मूल्य में परिवर्तन के बीच की विविधता प्रतिक्रिया की सीमा प्रतिस्थापन लोच द्वारा निर्धारित की जाती है। विभिन्न देश बाजार में आपूर्ति (निर्यात) करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मॉडल टैरिफ में कमी या व्यापार नीति में एक और बदलाव के बाद उस बाजार में आयात की संरचना और मात्रा में बदलाव का अनुकरण करता है। मूल्य में परिवर्तन के लिए प्रत्येक विदेशी निर्यातक की आपूर्ति की जवाबदेही की डिग्री को निर्यात आपूर्ति लोच के रूप में जाना जाता है।

**'स्मार्ट मॉडल'**, अनिवार्य रूप से, मानता है कि प्रत्येक विदेशी देश की निर्यात आपूर्ति लोच अनंत है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विदेशी देश एक निश्चित कीमत पर जितना संभव हो उतना अच्छा निर्यात कर सकता है। यह धारणा एक आयातक देश के लिए उपयुक्त हो सकती है जिसकी आयात मात्रा विदेशी निर्यातकों की कीमतों को प्रभावित करने के लिए बहुत कम है (अर्थात्, कीमत लेने वाली धारणा)। यदि देश की आयात मात्रा में परिवर्तन का विदेशी निर्यातक पर मूल्य प्रभाव पड़ सकता है, तो **'स्मार्ट'** सीमित निर्यात आपूर्ति लोच के साथ काम कर सकता है, लेकिन इस पैरामीटर का मूल्य विश्लेषण में पाया और शामिल किया जाना चाहिए। स्मार्ट मॉडल में, एक एफटीए वस्तु के मूल्य सूचकांक और विभिन्न राष्ट्रीय किस्मों की सापेक्ष कीमतों दोनों को प्रभावित करेगा।

**हाल के वर्षों में, अमेरिका, चीन और भारत के बीच आईओआर में सूक्ष्म भू-राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को श्रीलंका ने क्षेत्र में अपने सुरक्षा हितों के लिए संभावित खतरे के रूप में माना है।**

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि तीन देश हैं: ए, बी, और सी। ए बी और सी से एक सामान आयात करता है, लेकिन ए केवल बी के साथ एक एफटीए बना रहा है। पार्टनर बी से आयात पर टैरिफ कम करने से बी से आने वाली वस्तु के किस्म की घरेलू कीमत और कमोडिटी का मूल्य सूचकांक कम होगा। इसलिए घरेलू उपभोक्ता इस वस्तु की अधिक खरीद और आयात करना चाहेंगे। सी के सापेक्ष बी से आयात की सस्ती कीमत भी उपभोक्ताओं को सी से बी में अपने आयात की सोर्सिंग स्विच करने का कारण बनती है। '**स्मार्ट**' मॉडल में आयात का यह प्रतिस्थापन पूरी तरह से संतुलित है जिससे कि प्रतिस्थापन समग्र आयातित मात्रा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि नए सापेक्ष मूल्यों के आधार पर विदेशी भागीदारों के बीच बाजार शेयरों को आसानी से पुनः आवंटित करता है। हालाँकि, एफटीए के परिणामस्वरूप अधिमान्य व्यापार से लाभान्वित होने वाले देश या देशों से कम कीमतों के कारण आयात में वृद्धि होती है। संक्षेप में, आयातक देश आयात में वृद्धि का अनुभव करेगा, एफटीए निर्यात भागीदारों के निर्यात में वृद्धि होगी, और बाहरी लोगों को वस्तु के अपने निर्यात में गिरावट देखने को मिलेगी। व्यापार प्रभावों के अलावा, '**स्मार्ट**' टैरिफ राजस्व में भी परिवर्तन की गणना कर सकता है।

'**स्मार्ट**' को निम्नलिखित डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे डब्ल्यूआईटीएस से निकाला जा सकता है या एफटीए के अनुकरण के लिए सूचना के वैकल्पिक स्रोतों से आयात किया जा सकता है: (i) प्रत्येक विदेशी भागीदार से आयात मूल्य,(ii) प्रत्येक विदेशी भागीदार द्वारा भरा जाने वाला टैरिफ, (iii) कमोडिटी के लिए आयात माँग लोच, (iv) कमोडिटी के लिए निर्यात आपूर्ति लोच, और (v) कमोडिटी की किस्मों के बीच प्रतिस्थापन लोच।

**स्मार्ट सिमुलेशन परिणाम एक्सट्रैक्शन, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल के आयात में क्रमशः 4 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 1.18 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देते हैं। इस परिदृश्य में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के वैश्विक आयात में क्रमशः 1.12 प्रतिशत और 0.88 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।**

'**स्मार्ट**' अनुकरण मॉडल के संचालन के लिए आवश्यक सभी डेटा डब्ल्यूआईटीएस पर उपलब्ध है।

## अनुकरण परिदृश्य

- भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक दूसरे से आयात पर शुल्क हटाने के परिणामस्वरूप संभावित आर्थिक प्रभावों की जांच करने के लिए, दो काल्पनिक परिदृश्य सिम्युलेटेड हैं: परिदृश्य-1 भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ कटौती और भारत से आयात पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा 50% टैरिफ कटौती पर विचार करता है।
- • परिदृश्य-3 भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक दूसरे से आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ कटौती पर विचार करता है।

चार परिदृश्यों के आधार पर, हमने शुद्ध व्यापार प्रभावों, शुद्ध राजस्व प्रभावों के लिए इस समीकरण को प्रतिरूपित किया।

शुद्ध व्यापार प्रभाव (टीई) व्यापार निर्माण और व्यापार मोड़ प्रभाव का एक योग है:

टीई = टीसी + टीडी

नेट राजस्व प्रभाव (आरई) टैरिफ में बदलाव के बाद राजस्व में बदलाव दिखाता है। यह काफी हद तक आयात की कीमत और मात्रा पर निर्भर करता है।

$\Delta Rijk$

$Rijk$

$= \lfloor \Delta tijk$

$1 + tijk \rfloor$*n* $[1 + \beta\beta - n]$

जहाँ, $Rijk$ = टैरिफ परिवर्तनों के कारण राजस्व पर प्रभाव;$tijk$ =Tariff; n = the

## परिणाम और चर्चा

**परिदृश्य 1** ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय आयातों में 50 प्रतिशत की कटौती का अनुमान लगाते हुए, हमने ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत से आयात की जाने वाली शीर्ष (25) वस्तुओं का अनुकरण किया । सिमुलेशन परिणाम तालिका 8 में प्रस्तुत किए गए हैं । परिणाम बताते हैं कि भारतीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों की घरेलू कीमत में काफी गिरावट आई है । भारतीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट भारत के उच्च टैरिफ शासन की ओर संकेत करती है और इसलिए टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिशेष लाभ होता है । अनाज फसलों, मांस उत्पादों, निष्कर्षणों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, कपड़ा और पहनने वाले परिधानों, हल्के निर्माण और भारी विनिर्माण उत्पादों की कीमतों में 8-23 प्रतिशत और 13-53 प्रतिशत की गिरावट आई है। तालिका 8 से पता चलता है कि भारत के मामले में एचएस कोड 710239, (अन्य-डायमंड्स) 870322, (1000 सीसी से कम सिलेंडर क्षमता वाले वाहन), 847490 ( औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे) और 940360 (लकड़ी के फर्नीचर) वाले उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं में व्यापर निर्माण व्यापर परिवर्तन के प्रभाव पर हावी होता है ।

भारत के लिए व्यापार सृजन की सीमा विविध खाद्य रचनाओं, पेय पदार्थों, मशीनरी वस्तुओं, खनिजों, भारी इंजीनियरिंग वस्तुओं में सबसे अधिक है।

हमारे परिणाम संभावित भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए के तहत वैश्विक आयात भी दिखाते हैं। परिणाम भारत के मांस उत्पादों के वैश्विक आयात में 12.89 प्रतिशत, अनाज की फसलों में 1.65 प्रतिशत, कपड़ा और परिधान में 1.59 प्रतिशत और भारी विनिर्माण में 1.08 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, **'स्मार्ट'** अनुकरण परिणाम एक्सट्रैक्शन, टेक्सटाइल और पहनने वाले परिधान और भारी निर्माण के आयात में क्रमशः 4 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 1.18 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देते हैं। इस परिदृश्य में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के वैश्विक आयात में क्रमश: 1.12 प्रतिशत और 0.88 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, किसी भी दिशा में प्रभाव की गहनता अलग-अलग होती है और आम तौर पर लंबे समय में अधिक होती है।

### परिदृश्य 2

सिमुलेशन परिणाम से, आयात शुल्कों का पूर्ण उन्मूलन मानते हुए, यानी नई टैरिफ दर शून्य होगी, हम आयात और निर्यात में वस्तुवार प्रतिशत वृद्धि, कुल व्यापार प्रभाव जो व्यापार निर्माण और व्यापार परिवर्तन प्रभावों में विघटित होता है, पुरानी शुल्क दर, उपभोक्ता अधिशेष और एफटीए के कल्याणकारी प्रभाव पाते हैं।

---

हालांकि, एक औपचारिक रक्षा समझौते की कमी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बाधित नहीं किया है। श्रीलंका भारत के रक्षा सहयोग का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

---

तालिका 9 में प्रदर्शित परिणामों से पता चलता है कि भारत के मामले में व्यापार निर्माण लगभग सभी वस्तुओं में व्यापार व्युत्क्रम प्रभाव पर हावी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए कृषि और विनिर्माण दोनों तरह की कई वस्तुओं के मामले में महत्वपूर्ण व्यापार निर्माण का नेतृत्व नहीं करेगा। तालिका 9 से यह स्पष्ट है कि कल्याणकारी प्रभाव ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत के लिए बड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यापार निर्माण कल्याण में सुधार करता है क्योंकि नए आयात उच्च लागत वाले घरेलू उत्पादन को प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार निर्माण प्रभाव व्यापार को उच्च लागत वाले गैर-सदस्य देशों से कम लागत वाले सदस्य देशों में स्थानांतरित कर देता है।

**भारतीय निर्यात द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ**

अन्य विकसित देशों की तरह, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से विकसित विनियम हैं, जिनमें एनटीएम से संबंधित नियम शामिल हैं। घरेलू विधायी और नीतिगत आवश्यकताओं (राजस्व उद्देश्यों सहित) और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं (जापान के विदेश मामलों के मंत्रालय, 2016) के अनुपालन में, मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई , पशु और पौधों के जीवन की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, और आवश्यक सुरक्षा के कारणों से ऑस्ट्रेलिया विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार, अपने समाज की रक्षा के लिए आयात पर सख्ती से एनटीएम लगाता है। तालिका 10 ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए एनटीएम के प्रकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। तालिका ऑस्ट्रेलिया में एनटीएम की 1,897 घटनाओं की रिपोर्ट करती है। इनमें से, आयात-संबंधित एनटीएम का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है, जबकि शेष एनटीएम निर्यात-संबंधी हैं। ऑस्ट्रेलिया के आयात एनटीएम, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) समझौते (अध्याय ए), और टीबीटी (अध्याय बी) द्वारा कवर किए गए उपायों सहित तकनीकी विनियमों और मानकों के अनुरूपता का आकलन करने के लिए तकनीकी विनियमों और प्रक्रियाओं का सन्दर्भ लेते हुए, ज्यादातर तकनीकी उपाय हैं।

तकनीकी उपाय (अर्थात अध्याय ए, बी, सी, और पी में कुछ) आयात एनटीएम के 93 प्रतिशत या कुल एनटीएम के 70 प्रतिशत हैं, गैर-तकनीकी उपाय केवल 7 प्रतिशत हैं । जैसा कि तालिका 10 में दिखाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में एनटीएम का सबसे आम प्रकार टीबीटी है, जो कुल का 55 प्रतिशत है, इसके बाद निर्यात उपाय (25%), और एसपीएस उपाय (15%) हैं । गैर-तकनीकी उपायों में मूल्य नियंत्रण उपाय शामिल हैं।

## तालिका 10:

अध्याय द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए गैर-टैरिफ उपायों के प्रकार

| एनटीएम के प्रकार | कोडेड एनटीएम की संख्या | कुल एनटीएम का प्रतिशत (%) | प्रभावित उत्पादों (राष्ट्रीय टेरिफ लाइनों की संख्या | (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| स्वच्छता और फाइटोसैनेटिक उपाय | 293 | 15.39 | 6184 | 100 |
| व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएँ | 1035 | 54.56 | 6184 | 100 |
| शिपमेंट-पूर्व निरीक्षण और अन्य औपचारिकताएँ | 6 | 0.32 | 6184 | 100 |
| आकस्मिक व्यापार-सुरक्षा उपाय | 0 | 0 | | |
| गैर-स्वचालित लाइसेंसिंग, कोटा, | | | | |
| निषेध और मात्रा नियंत्रण उपाय | | | | |
| सेनेटरी और फाइटोसैनेटिक उपायों | 18 | 0.95 | 185 | 2.99 |
| या व्यापार कारणों की तकनीकी बाधा के अलावा | | | | |
| अतिरिक्त कर और शुल्क सहित मूल्य नियंत्रण उपाय | 77 | 4.06 | 6185 | 100 |
| वित्त उपाय | 0 | 0 | | |
| प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले उपाय | 0 | 0 | | |
| व्यापार - संबंधित निवेश उपाय | 0 | 0 | | |
| वितरण प्रतिबंध | 0 | 0 | | |
| बिक्री के बाद की सेवाओं पर प्रतिबंध | 0 | 0 | | |
| सब्सिडी (पी 7 के तहत निर्यात सब्सिडी को छोड़कर) | 0 | 0 | | |
| सरकारी खरीद प्रतिबंध | 0 | 0 | | |
| बौद्धिक संपदा | 1 | 0.05 | 43 | 0.7 |
| उत्पत्ति के नियम | 0 | 0 | | |
| निर्यात संबंधी उपाय | 468 | 24.67 | 6184 | 100 |

स्रोत: यूएनसीटीएडी *(2020)* पीपी*18* से अपनाया गया

मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाने के लिए इनमें से कई एनटीएमएस में ढील देने की तत्काल आवश्यकता है । टैरिफ छूट के साथ मिलकर एनटीएम के संबंध में केवल एक अनुकूल नीति इन दो उभरते भागीदारों के बीच व्यापार को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

## निष्कर्ष

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक एफटीए का अनुसरण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार अपनी क्षमता से बहुत कम है और यदि नीतियों को, विशेष रूप से उदार टैरिफ दरों को अपनाकर अनुकूल रूप से तैयार किया जाता है, तो इसे काफी बढ़ाया जा सकता है। दोनों देशों का मानना है कि एक दूसरे को अधिमान्य व्यापारिक अधिकार देकर इस अवसर का दोहन किया जा सकता है। प्रस्तावित एफटीए इसी दिशा में एक कदम है। वर्तमान अध्ययन में व्यापार की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है जिसे टैरिफ दरों में छूट देकर प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्ययन दो काल्पनिक स्थितियों के साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया गया है। हमने टैरिफ दरों में 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया और एफटीए के बाद की अवधि में व्यापार के संभावित निर्माण और परिवर्तन का अनुमान लगाया । अध्ययन ने उन संभावित लाभों का पता लगाने की कोशिश की जो भारत व्यापार वार्ता से प्राप्त कर सकता है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई पूरकताओं से प्रेरित है । वस्तुओं और सेवाओं में दो-तरफा व्यापार 2007 में 13.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020 में 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है । वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने क्षेत्रों की सूची पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार और आर्थिक रूपरेखा (टीईएफ) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ।

विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय टैरिफ ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत अधिक हैं। उच्च टैरिफ के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया से भारतीय आयात समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, इस तथ्य को दर्शाता है कि टैरिफ व्यापार को कम करने या बढ़ाने के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं हैं। भारत के पास अपनी टैरिफ दर को कम करने और ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर तरजीही शुल्कों की पेशकश करने की बहुत गुंजाइश है। शीर्ष आयातित वस्तुओं में भारत की उच्चतम टैरिफ दर खाद्य सब्जियों (एचएस 07) पर लागू 90 प्रतिशत से अधिक है जबकि उर्वरकों (एचएस 31) पर सबसे कम दर 5 प्रतिशत है। उच्चतम ऑस्ट्रेलियाई टैरिफ दर 42.06 है जो परिधान कला और कपड़ा पहुँच (एचएस 61) पर लागू होती है और न्यूनतम टैरिफ दर 1.61 प्रतिशत खनिज ईंधन (एचएस 27) पर लगाई जाती है।

टीआईआई विश्लेषण से पता चलता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार विश्व व्यापार में उनकी सापेक्ष स्थिति को देखते हुए इसकी क्षमता से बहुत कम है। यह भविष्य में इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच उच्च व्यापार की संभावना को दर्शाता है।

टैरिफ उन्मूलन के संभावित प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए, अध्ययन '**स्मार्ट**' (बाजार विश्लेषण और व्यापार पर प्रतिबंध के लिए सॉफ्टवेयर) मॉडल लागू करता है। मॉडल की भविष्यवाणियां अतीत में देखे गए व्यापार-उदारीकरण के अनुभवों के अनुरूप हैं, निर्यात क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है और आयात क्षेत्रों में कीमतें गिर रही हैं। भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है और ईंधन निर्यात में भारी रूप से केंद्रित हो गया है, जबकि आयात में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो मूल रूप से अधिक संरक्षित थे।

टैरिफ में 50 प्रतिशत कटौती के परिणाम संकेत देते हैं कि भारतीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों की घरेलू कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। भारतीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट भारत के उच्च टैरिफ शासन की ओर संकेत करती है और इसलिए टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिशेष लाभ होता है।

अनाज फसलों, मांस उत्पादों, निष्कर्षणों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, कपड़ा और पहनने वाले परिधानों, हल्के निर्माण और भारी विनिर्माण उत्पादों की कीमत में 8–23 प्रतिशत और 13–53 प्रतिशत की सीमा में गिरावट आई है।

100 प्रतिशत टैरिफ कटौती के परिणाम बताते हैं कि भारत के मामले में लगभग सभी जिंसों में व्यापार निर्माण व्यापर परिवर्तन प्रभाव पर हावी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए कृषि और विनिर्माण दोनों तरह की कई वस्तुओं के मामले में महत्वपूर्ण व्यापार निर्माण की ओर नहीं बढ़ेगा।

## तालिका 8:

**भारतीय परिप्रेक्ष्य से 50% टैरिफ कटौती के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए में व्यापार प्रभाव**

| उत्पाद कोड (एचएस) | व्यापार कुल प्रभाव | व्यापार निर्माण प्रभाव | व्यापार परिवर्तन प्रभाव | पुरानी सरल ड्यूटी दर | नई सरल ड्यूटी दर | वेलफेयर प्रभाव | राजस्व प्रभाव | उपभोक्ता अधिशेष | आयात परिवर्तन | निर्यात परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300490 | 27367.02 | 26766.94 | 600.07 | 30.00 | 21.00 | 6905.81 | 3886.93 | 4160.32 | 26766.94 | 27367.02 |
| 100630 | 36765.53 | 25890.32 | 10875.21 | 35.50 | 24.85 | 20978.65 | -1403.37 | 5953.59 | 25890.32 | 36765.53 |
| 711319 | 14610.87 | 8797.29 | 5813.58 | 36.67 | 25.67 | 2834.35 | -4277.78 | 1966.12 | 8797.29 | 14610.87 |
| 90111 | 8433.13 | 5420.48 | 3012.66 | 3.33 | 2.33 | 139.48 | -562.51 | 97.18 | 5420.48 | 8433.13 |
| 380893 | 5667.24 | 5215.28 | 451.96 | 43.33 | 30.33 | 2730.04 | 1583.90 | 1868.63 | 5215.28 | 5667.24 |
| 630260 | 5368.15 | 5150.17 | 217.98 | 32.86 | 23.00 | 522.53 | 854.60 | 1456.31 | 5150.17 | 5368.15 |
| 630532 | 5035.76 | 4253.25 | 782.51 | 6.90 | 4.83 | 548.35 | -9413.67 | 61.52 | 4253.25 | 5035.76 |
| 940490 | 4327.24 | 3851.50 | 475.75 | 4.60 | 3.22 | 113.93 | -541.40 | 26.76 | 3851.50 | 4327.24 |
| 760120 | 4464.96 | 3781.82 | 683.13 | 4.28 | 2.99 | 213.26 | -886.47 | 20.69 | 3781.82 | 4464.96 |
| 860310 | 11330.55 | 3590.98 | 7739.57 | 2.23 | 1.56 | 352.73 | -688.94 | 16.02 | 3590.98 | 11330.55 |
| 940360 | 4086.27 | 3224.12 | 862.15 | 0.35 | 0.25 | 49.86 | -160.35 | 11.63 | 3224.12 | 4086.27 |
| 610910 | 1948.39 | 1691.10 | 257.29 | 57.71 | 40.40 | 1332.38 | 642.08 | 625.62 | 1691.10 | 1948.39 |
| 732591 | 2248.70 | 1577.15 | 671.56 | 29.00 | 20.30 | 265.40 | -333.74 | 372.47 | 1577.15 | 2248.70 |
| 210690 | 2616.46 | 1506.40 | 1110.06 | 29.90 | 20.93 | 282.19 | -978.26 | 307.38 | 1506.40 | 2616.46 |
| 630419 | 1143.48 | 951.95 | 191.53 | 0.27 | 0.19 | 26.39 | -520.40 | 1.98 | 951.95 | 1143.48 |
| 570231 | 1110.46 | 703.79 | 406.67 | 5.78 | 4.05 | 33.53 | -507.21 | 17.07 | 703.79 | 1110.46 |
| 710239 | 1189.22 | 580.83 | 608.39 | 30.00 | 21.00 | 145.18 | -1109.56 | 128.08 | 580.83 | 1189.22 |
| 570500 | 782.94 | 474.54 | 308.40 | 0.89 | 0.62 | 1.62 | -237.64 | 3.34 | 474.54 | 782.94 |
| 870322 | 594.02 | 248.58 | 345.44 | 13.83 | 9.68 | 17.12 | -229.61 | 7.55 | 248.58 | 594.02 |
| 420221 | 308.32 | 133.71 | 174.61 | 3.89 | 2.72 | 1.46 | -305.05 | 1.76 | 133.71 | 308.32 |
| 630492 | 385.55 | 128.99 | 256.56 | 5.48 | 3.84 | 2.94 | -136.78 | 0.72 | 128.99 | 385.55 |
| 860500 | 145.41 | 108.36 | 47.14 | 41.43 | 29.00 | 39.38 | -56.14 | 34.66 | 108.36 | 155.50 |
| 620442 | 149.88 | 90.43 | 59.45 | 3.01 | 2.10 | 1.68 | -14.14 | 0.95 | 90.43 | 149.88 |
| 271012 | 76.24 | 63.48 | 12.76 | 18.33 | 12.83 | 2.68 | -7.14 | 19.42 | 63.48 | 76.24 |
| 847490 | 104.87 | 60.94 | 43.93 | 0.42 | 0.29 | 0.59 | -62.70 | 0.14 | 60.94 | 104.87 |
| 271019 | 55.23 | 54.64 | 10.60 | 37.78 | 26.44 | 26.27 | -3.74 | 14.44 | 54.64 | 65.25 |
| 300410 | 81.74 | 28.15 | 53.59 | 1.14 | 0.80 | 0.11 | -29.13 | 0.14 | 28.15 | 81.74 |
| 730630 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 30.00 | 21.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |

## तालिका 9:

**भारतीय परिप्रेक्ष्य से 100% टैरिफ कटौती के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया एफटीए में व्यापार प्रभाव**

| क्रम सं. | उत्पादन कोड | व्यापार कुल प्रभाव | व्यापार निर्माण प्रभाव | व्यापार परिवर्तन प्रभाव | पुरानी सरल शुल्क दर | वेलफेयर प्रभाव | राजस्व प्रभाव | उपभोक्ता अधिशेष | आयात परिवर्तन | निर्यात परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 100630 | 193620.03 | 133002.92 | 60617.11 | 36.14 | 30659.71 | -152715.94 | 30727.15 | 3.77 | 67.44 |
| 20 | 860310 | 133626.80 | 111123.88 | 22502.92 | 38.00 | 23884.52 | -91760.11 | 27395.92 | 43.44 | 117.98 |
| 2 | 300490 | 104139.44 | 101368.07 | 2771.37 | 30.00 | 16239.50 | -7020.53 | 14438.42 | 86.72 | 495.03 |
| 21 | 940490 | 93531.89 | 75715.45 | 17816.44 | 109.38 | 48004.51 | -129000.66 | 75152.26 | 9.81 | 28.84 |
| 9 | 380893 | 19038.48 | 17768.81 | 1269.67 | 42.50 | 6363.15 | -2222.11 | 5088.73 | 19.21 | 644.05 |
| 16 | 420221 | 20115.60 | 14362.51 | 5753.10 | 38.46 | 3130.22 | -8584.40 | 6040.74 | 1.72 | 80.63 |
| 8 | 610910 | 12651.24 | 10821.35 | 1829.88 | 53.78 | 5937.45 | -3646.50 | 3803.79 | 1.13 | 369.89 |
| 11 | 732591 | 13267.76 | 10274.81 | 2992.95 | 23.89 | 1389.95 | -3037.96 | 2240.50 | 1.58 | 76.44 |
| 22 | 940360 | 21395.48 | 10108.93 | 11286.55 | 18.57 | 2235.45 | -12952.02 | 588.77 | 1.28 | 60.95 |
| 10 | 630260 | 10386.29 | 9545.00 | 841.29 | 33.53 | 463.93 | -1208.71 | 2383.71 | 10.03 | 458.11 |
| 27 | 570231 | 9479.40 | 7864.46 | 1614.94 | 1.85 | 1278.52 | -1860.29 | 83.13 | 0.07 | 11.99 |
| 6 | 711319 | 20061.10 | 7828.01 | 12233.08 | 33.94 | 3269.30 | -17792.12 | 1643.49 | 0.60 | 78.94 |
| 4 | 710239 | 9775.10 | 7611.80 | 2163.30 | 30.00 | 1123.35 | -10816.95 | 1499.09 | 13.55 | 28.83 |
| 12 | 210690 | 10027.55 | 6090.33 | 3937.22 | 29.96 | 1043.80 | -6967.26 | 1217.47 | 2.03 | 48.44 |
| 19 | 630419 | 7064.49 | 4002.81 | 3061.68 | 34.68 | 773.99 | -4864.58 | 1036.25 | 2.76 | 52.86 |
| 17 | 630532 | 4632.72 | 3005.43 | 1627.29 | 30.00 | 580.21 | -1734.93 | 451.19 | 0.95 | 98.18 |
| 14 | 870322 | 4292.96 | 2312.86 | 1980.10 | 20.36 | 379.90 | -2930.31 | 350.92 | 0.01 | 31.47 |
| 24 | 300410 | 2889.49 | 1642.74 | 1246.75 | 11.91 | 151.26 | -1035.38 | 50.93 | 0.08 | 31.83 |
| 18 | 630492 | 951.94 | 515.17 | 436.76 | 31.25 | 87.02 | -458.40 | 75.89 | 0.48 | 71.88 |
| 3 | 860500 | 552.19 | 322.91 | 229.28 | 40.00 | 100.07 | -389.96 | 89.59 | 0.72 | 69.17 |
| 1 | 271019 | 193.94 | 187.38 | 6.56 | 53.33 | 92.09 | -70.26 | 44.07 | 3.49 | 222.23 |
| 15 | 847490 | 201.87 | 165.05 | 36.82 | 30.00 | 33.20 | -155.25 | 38.33 | 2.98 | 41.94 |
| 28 | 271019 | 545.97 | 160.81 | 385.16 | 2.53 | 2.98 | -270.70 | 0.91 | 0.00 | 0.55 |
| 25 | 760120 | 174.14 | 53.26 | 120.89 | 0.07 | 0.28 | -83.39 | 0.12 | 0.00 | 1.17 |
| 5 | 271012 | 72.37 | 43.16 | 29.21 | 11.25 | 1.87 | -22.83 | 12.61 | 0.15 | 18.65 |
| 13 | 730630 | 32.75 | 9.95 | 22.80 | 30.00 | 0.03 | -17.63 | 1.78 | 0.01 | 55.88 |
| 23 | 570500 | 0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 90111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# REFERENCES


- Abrams, R. K. (1980). International trade flows under flexible exchange rates. Economic Review, 65(3), 3-10.
- Agarwal, M. and Ghosh, S. (2017). The Effect of Regional Trade Agreements on India's Trade, in Agarwal, M. etal. (Ed.) *The Economies ofi China and India*, Vol.1, World Scientific, Singapore
- Ahmed, S. (2011). Economic and welfare impacts of prospective India–Australia FTA using GTAP and SMART models. *Iníernaíional Journal ofi Business and Emerging Markeís*, Vol. 3, No. 4, pp.396–417.
- Aitken, N. D. (1973). The effect of the EEC and EFTA on European trade: A temporal cross-section analysis. *The American Economic Review*, 881-892.
- Baldwin, RE. and Seghezza, E. (2007). Are trade blocs building or stumbling blocks? New evidence. *CEPR Discussion Paper 6599.* Washington D.C
- Baldwin, RE. (1993). A domino theory of regionalism. *NBER Working Paper No. 4465*, Cambridge, MA.
- Baldwin, RE. (1997). *The causes ofi regionalism. The World Economy*, vol. 20, no.7, pp. 865-88.
- Baldwin, RE. (2011). 21st century regionalism: filling the gap between 21st century trade and 20th century trade rules. *WTO ERSD Síafifi Working Papers, no. 8*, World Trade Organisation, Geneva.
- Bergstrand, J. (1985). The gravity equation in international trade: some microeconomic foundation and empirical evidence. *The Review ofi Economics and Síaíisíics 67,* 474– 481.
- Bhagwati, J. N. (2014). The world trading system at risk. Princeton University Press.
- Bhagwati, J., & Krueger, A. O. (1995). The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements (Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research).

- Bhagwati, J. and Panagariya, A. (1996). Preferential trading areas and multilateralism: strangers, friends or foes? in *The economics ofi prefiereníial írade agreemenís, (eds.)* J Bhagwati & A Panagariya, AEI Press, Washington D.C.
- Brada, J. C. & Mendez, J. A. (1985). Economic integration among developed, developing and centrally planned economies: A comparative analysis. *The Review ofi Economics and Síaíisíics,* 549-556.
- Brewster, D. (2015). The Australia–India Framework for Security Cooperation: Another Step towards an *Indo-Pacific Securiíy Parínership. Securiíy Challenges, Vol. 11, No. 1,* pp. 39-48
- Brewster, D. (2015). The Australia–India framework for security cooperation: another step towards an *Indo-Pacific securiíy parínership. Securiíy Challenges, 11(1),* 39-48.
- Cho S. W. & Yoon G. (2014). Sectoral analysis of an *Ausíralia–India firee írade agreemení. Journal ofi íhe Asia Pacific Economy, 19:2,* pp.205-229
- Choudhury, R. (September 21, 2021). High time India and Australia resume FTA negotiations to seal a conclusive deal. *Souíh Asia Moniíor.* Available at: https://www.southasiamonitor.org/spotlight/high-time-india-and-australia-resume-fta-negotiations-seal-conclusive-deal Accessed on 10.12.21
- Estevadeordal, A., López-Córdova, E. &Suominen, K. (2006). How do rules of origin affect investment flows? Some hypotheses and the case of Mexico. *INTAL-ITD Working Paper 22,* INTAL, Buenos Aires.
- Francis, S. (2011). A Sectoral Impact Analysis of the ASEAN-India Free Trade Agreement. *Economic and Poliíical Weekly,* (46)46-55
- Frankel, J. A., Stein, E., & Wei, S. J. (1997). *Regional írading blocs in íhe world economic sysíem.* Peterson Institute.
- Frankel, J., Stein, E., & Wei, S. J. (1995). Trading blocs and the Americas: The natural, the unnatural, and the super-natural. *Journal ofi developmení economics, 47(1),* 61-95.

- Ghosh, S., &Yamarik, S. (2004). Are regional trading arrangements trade creating? An application of extreme bounds analysis. *Journal ofi Iníernaíional Economics, 63(2),* 369-395.
- Grossman, G. &Helpman, E. (1995). The politics of free-trade agreements. *American Economic Review, (85) 4,* pp. 667-90.
- Hewett, E. A. (1976). A gravity model of CMEA trade. *Quaníiíaíive and analyíical síudies in Easí-Wesí economic relaíions,* 1-15.
- Jha, S. (2011). Preferential Trade and Rules of Origin: A study of India's Preferential Trading Arrangements. Unpublished PhD Thesis, *Indian Insíiíuíe ofi Foreign Trade New Delhi.*
- Joshi, V. (2010). An econometric analysis of India-Sri Lanka free trade agreement, HEID Working Paper, No. 04/2010, *Graduaíe Insíiíuíe ofi Iníernaíional and Developmení Síudies,* Geneva
- Kelegama, S. and Karunaratne, C. (2013). Experiences of Sri Lanka in the Sri Lanka – India FTA and the Sri Lanka – Pakistan FTA. *Regional Value Chains Background Paper No 10,* UNCTAD. Geneva.
- Krishna, P. (1998). Regionalism and multilateralism: A political economy approach. *The Quaríerly Journal ofi Economics, 113(1),* 227-251.
- Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *The American Economic Review, 70(5),* 950-959.
- Levy, PI (1997). A political-economic analysis of free trade agreements. *American Economic Review, (87) 4,* pp. 506-19.
- Limão, N. (2006). Preferential trade agreements as stumbling blocks for multilateral trade liberalization: Evidence for the United States. *American Economic Review, 96(3),* 896-914.
- Lipsey, R. G. (1970). *The íheory ofi cusíoms unions: A general equilibrium analysis.* Weidenfeld and Nicolson.
- Meade, J. E. (1955). *The Theory ofi Cusíom Unions. Amsíerdam,* the North Holland Publishing Co.

- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2018). Available at https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/study0504/index.html (accessed 2 May 2022).
- Nag, B., and Sikdar, C. (2011). Welfare implication of India-ASEAN FTA: An analysis using GTAP model. *Indian Insíiíuíe ofi Foreign Trade Working Paper No. EC-11-06.*
- Panda, R. and Baruah, P. (2010). India–Australia Strategic Partnership A Case for *Holisíic Approach. India Quaríerly, 66(2),* pp.203–221
- Plummer, M. G., Cheong, D., Hamanaka, S. (2010). *Meíhodology fior impací assessmení ofi Free Trade Agreemenís'*. Asian Development Bank, Manila.
- S. Alam et al. (2013).The Australia India Proposed Free Trade Agreement and Trade in Agriculture: Opportunities and Challenges. *The Journal ofi World Invesímení & Trade. 14,* pp.167–197
- Summers, L. (1991). Regionalism and the world trading system. *Policy implicaíions ofi írade and currency zones,* 295-301.
- Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy; suggestions for an international economic policy.
- UNCTAD (2020). Non-Tariff Measures in Australia, China, India, Japan, New Zealand and *íhe Republic ofi Korea: Preliminary Findings,* UNCTAD
- Viner, J. (1950), The Customs Union Issue, reproduced in *Economic Analysis ofi Regional Trading Arrangemenís, ed R Pomfireí (2003)*, Edward Elgar, UK.

| अनुलग्नक 1 | | | |
|---|---|---|---|
| **आरटीए का नाम** | **वर्तमान सदस्य** | **प्रभाव में आने की प्रवेश तिथि** | **कालक्रम** |
| | | | |
| एफटीए और ईआईए | | | |
| भारत-जापान एफटीए और ईआईए | भारत और जापान | अगस्त 1,2011 | |
| भारत-मलेशिया एफटीए और ईआईए | भारत और मलेशिया | जुलाई 1, 2011 | |
| भारत-सिंगापुर एफटीए और ईआईए | भारत और सिंगापुर | अगस्त 1, 2005 | |
| भारत-दक्षिण कोरिया एफटीए और ईआईए | भारत और दक्षिण कोरिया | जनवरी 1, 2010 | |
| एफटीए | | | |
| भारत-आसियानएफटीए | कंबोडिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, भारत, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, द फिलीपींस और वियतनाम | जुलाई 1,2004 | भारत, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड (जनवरी 1, 2010) ब्रुनेई दारुस्सलाम, म्यांमार और वियतनाम (1 जून, 2010), इंडोनेशिया (अक्टूबर 1, 2010), लाओ पीडीआर (जनवरी 1, 2011), कंबोडिया (15 जुलाई, 2011) |
| भारत-भूटान एफटीए | भारत और भूटान | जून 30, 2008 | |
| साफ्टा | बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका | जनवरी 6, 2004 | व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम 1 जनवरी, 2006 से शुरू हुआ |
| भारत- मॉरीशस सीईसीपीए | भारत और मॉरीशस | अप्रैल 2021 | |
| पीएसए | | | |
| भारत-अफगानिस्तान पीएसए | भारत और अफगानिस्तान | मई 13, 2003 | |
| भारत एपीटीएपीएसए | बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, दक्षिण कोरिया, श्री लंका | जून 17, 1976 | बीए हस्ताक्षरित: 1975 (भारत, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, लाओ पीडीआर, श्रीलंका) बीए जून 17,1976 में प्रभाव में आया: चीन का परिग्रहण : 1 जनवरी, 2002, एपीटीए नाम बदलना: 2005, संशोधित समझौता: 1 सितंबर, 2006 |
| भारत-चिली पीएसए | भारत और चिली | अगस्त 17, 2007 | भारत में समझौता प्रभावी ढंग से सितंबर 11,2007 को लागू हुआ |
| भारत-मर्कोसुर पीएसए | भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे | जून 1, 2009 | 17 जून, 2003 को एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे 25 जनवरी, 2004 को तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, वेनेजुएला इस समझौते का एक हिस्सा नहीं है। |
| भारत-नेपाल पीएसए | भारत और नेपाल | अक्टूबर 27, 2009 | |

स्रोत:अग्रवाल और घोष 2017 से लिया गया

अनुलग्नक 2

**2019-20** में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष **50** भारतीय निर्यात सामान (मिलियन अमरीकी डॉलर )

| एचएस कोड | उत्पादन विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 271019 | अन्य पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज आदि से प्राप्त तेल | 16969 |
| 710239 | अन्य | 16553 |
| 300490 | खुदरा बिक्री के लिए रखी गई अन्य दवाएँ | 14812 |
| 271012 | हल्के तेल और उससे बनी वस्तुएँ : | 8245 |
| 100630 | सेमी/पूरे माइल्ड राइस डब्ल्यू / एन पॉलिश्ड/ग्लेज्ड | 8030 |
| 711319 | अन्य कीमती मेटल की वस्तुएँ डब्ल्यू/एन प्लेटेड या क्लैड | 4827 |
| 30617 | अन्य श्रिम्प और झींगे: जमे हुए | 3855 |
| 760110 | एल्युमीनियम-मिश्रित नहीं | 3536 |
| 851712 | सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन: | 3105 |
| 260111 | रोस्टेड लोहे के पायराइट्स के अलावा लौह अयस्क और सांद्र गैर-समूहीकृत | 3100 |
| 20230 | बिना हड्डी का | 2852 |
| 890590 | अन्य पोत, फायर फ्लोट आदि | 2578 |
| 841112 | एक थ्रस्ट के टर्बो-जेट>25 नॉट | 2405 |
| 870899 | एचडीजी 8701-8705 के वाहनों के अन्य पार्ट्स और एक्सेसरीज | 2359 |
| 720839 | <3एमएम एनटी की मोटाई के कॉइल्स में फ्लैट-रोल्ड प्रोडक्ट्स गर्म रोल्ड एक्सेल पैक्लड | 2122 |
| 870322 | सिलेंडर क्षमता> 1000 सीसी बीटी एनटी> 1500 सीसी के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन वाले वाहन | 1989 |
| 170199 | शुगर रिफाइंड एनटी कंटेनिंग फेवरिंग /रंग पदार्थ | 1910 |
| 260112 | लौह अयस्क और संकेंद्रित सांद्र | 1796 |
| 520100 | कपास, कार्डेड या कॉम्बेड नहीं | 1780 |
| 871120 | रेसिप्रोकेटिंग के साथ सिलेंडर कैपेसिटी >50 सीसी से 250 सीसी के आंतरिक कम्बसशन पिस्टन इंजन के मोटर साइकिल आदि | 1779 |
| 711311 | ज्वेल पार्ट्स की वस्तुएँ और उनके चाँदी के पार्ट्स अन्य कीमती मेटल से प्लेटेड/क्लेडेड या उसके बिना | 1766 |
| 720719 | वजन <0.25% कार्बन से युक्त अन्य उत्पाद | 1682 |
| 290243 | पी- जाइलिन | 1554 |
| 610910 | कॉटन की टी-शर्ट आदि | 1470 |
| 380891 | कीटनाशक | 1344 |
| 380893 | हर्बिसाइड्स, अंकुरण रोधी उत्पाद और पौधों की वृद्धि विनियमित: | 1289 |
| 294200 | अन्य कार्बनिक यौगिक: सेफैड्रॉक्सिल और इसके साल्ट, इबुप्रोफेन, निफेडिपिन, रैनिटिडिन, डेन्स साल्ट ऑफ डी (-) फेनी | 1271 |
| 300420 | अन्य, एंटीबायोटिक्स युक्त | 1219 |

स्रोत : व्यापर व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

| एचएस कोड | उत्पादन विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 230400 | तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष सोया-बीन तेल निकालने से प्राप्त ग्राइंड /इन प्लेट्स फॉर्म में | 1135 |
| 870323 | सिलेंडर क्षमता> 1500 सीसी बीटी <= 3000 के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन पारस्परिक इंजन वाले वाहन | 1088 |
| 870321 | सिलेंडर क्षमता <= 1000 के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन पारस्परिक इंजन वाले वाहन | 1088 |
| 690721 | 0.5% से अधिक वजन के नहीं जल अवशोषण गुणांक | 1074 |
| 850440 | स्थिर कन्वर्टर्स | 1074 |
| 630260 | टेरी टॉवेलिंग/समान टेरी फैब्रिक्स, कॉटन के टॉयलेट लिनन और किचन लिनन | 1044 |
| 630419 | अन्य चादरें | 1013 |
| 90421 | सूखे, न कुचले और न ही ग्राइंड :जीनस शिमला मिर्च या जीनस पिमेंटा के फल | 970 |
| 293399 | केवल नाइट्रोजन के साथ अन्य विषमचक्रीय यौगिक हेट्रोएटम (एस) | 930 |
| 300220 | मानव चिकित्सा के लिए टीके | 879 |
| 880330 | हवाई जहाज या हेलीकाप्टर के अन्य भाग | 878 |
| 151530 | अरंडी का तेल और इसके अंश | 848 |
| 720711 | वजन <0.25% के कार्बन युक्त उत्पादन आयात (वर्गाकार सहित) Crs-Sctn; मोटाई से दुगुनी चौड़ाई | 842 |
| 520523 | < 232.56 but >=192.31 Dctx (>43 But <=52 Mtrc No) माप के कंबाइंड फाइबर का सिंगल यार्न | 834 |
| 680223 | समतल/समान सतह की सामान्य Cut/Swn वाला ग्रेनाइट | 824 |
| 401170 | कृषि या वानिकी वाहनों और मशीनों पर प्रयुक्त एक प्रकार का | 814 |
| 293339 | अन्य: पाइरीडीन के संजात: | 807 |
| 320417 | पिगमेंट और उसके आधार पर तैयार | 785 |
| 630492 | कॉटन, एनटीकेएनटीडी/सीआरचटीडी की अन्य फर्निशिंग सामग्री | 774 |
| 848180 | अन्य उपकरण: | 768 |
| 290220 | बेंजीन | 755 |
| 760120 | एल्यूमीनियम मिश्र | 739 |

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

## अनुलग्नक 3

**2019-20** में ऑस्ट्रेलिया से भारत के शीर्ष **50** आयात की जाने वाली वस्तुएँ (मिलियन अमरीकी डॉलर)

| एचएस कोड | उत्पादन विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 271019 | अन्य पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज आदि से प्राप्त तेल | 16969 |
| 710239 | अन्य | 16553 |
| 300490 | खुदरा बिक्री के लिए रखी गई अन्य दवाएँ | 14812 |
| 271012 | हल्के तेल और उससे निर्मित : | 8245 |
| 100630 | सेमी/पूरी तरह से माइल्ड चावल पॉलिश्ड/ग्लेज्ड या उसके बिना | 8030 |
| 711319 | अन्य कीमती मेटल के प्लेटेड या क्लैड की गई /या उसके बिना वस्तुएँ | 4827 |
| 30617 | अन्य चिंराट और झींगे: फ्रोजेन | 3855 |
| 760110 | एल्युमीनियम-मिश्रित नहीं | 3536 |
| 851712 | सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन: | 3105 |
| 260111 | रोस्टेड लोहे के पायराइट्स के अलावा लौह अयस्क और सांद्र गैर-समूहीकृत | 3100 |
| 20230 | बिना हड्डी का | 2852 |
| 890590 | अन्य वेसल्स, फायर फ्लोट आदि | 2578 |
| 841112 | एक थ्रस्ट >25 के टर्बो-जेट | 2405 |
| 870899 | एचडीजी 8701-8705 के व्हीकल के अन्य पार्ट्स और एक्सेसरीज | 2359 |
| 720839 | <3एमएम के कॉइल्स में फ्लैट रोल्ड उत्पाद Nt Frthr Wrkd Thn Hot-Rold Excl Pckld | 2122 |
| 870322 | सिलेंडर क्षमता> 1000 सीसी बीटी एनटी> 1500 सीसी के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन वाले वाहन | 1989 |
| 170199 | रिफाइंड शुगर बिना कॉन्टेंज फ्रवर्नग/कोलरिंग मैटर के | 1910 |
| 260112 | लौह अयस्क और संकेंद्रित सांद्र | 1796 |
| 520100 | कॉटन, कार्डेड या कॉम्बेड नहीं | 1780 |
| 871120 | सिलेंडर क्षमता >50 सीसी से 250 सीसी के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन वाले मोटर साइकिल आदि | 1779 |
| 711311 | **ज्वेल पार्ट्स की वस्तुएँ और उनके चाँदी के पार्ट्स अन्य कीमती मेटल से प्लेटेड/क्लेडेड या उसके बिना** | 1766 |
| 720719 | वजन <0.25% के कार्बन से युक्त अन्य उत्पाद | 1682 |
| 290243 | पी जाइलिन | 1554 |
| 610910 | कॉटन की टी-शर्ट आदि | 1470 |
| 380891 | कीटनाशक | 1344 |
| 380893 | हर्बिसाइड्स, एंटी-स्प्राउटिंग उत्पाद और प्लांट-ग्रोथ रेगुलेटेड: | 1289 |
| 294200 | अन्य कार्बनिक यौगिक: सेफैड्रॉक्सिल और इसके साल्ट, इबुप्रोफेन, निफेडिपिन, रैनिटिडीन, डेन्स साल्ट ऑफ डी (-) फेनी | 1271 |
| 300420 | अन्य, एंटीबायोटिक्स युक्त | 1219 |

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

| एच एस कोड | उत्पाद विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 230400 | सोया-बीन तेल निकालने से प्राप्त तेल-खली और अन्य ठोस अवशेष ग्राइंड/पिल्ट्स रूप में या उसके बिना | 1135 |
| 870323 | सिलेंडर क्षमता> 1500 सीसी बीटी <= 3000 के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन पारस्परिक इंजन वाले वाहन | 1088 |
| 870321 | सिलेंडर क्षमता <=1000 सीसी के स्पार्क-इग्निशन आंतरिक दहन पारस्परिक पिस्टन वाले वाहन | 1088 |
| 690721 | 0.5% से अधिक नहीं वजन से जल अवशोषण गुणांक का | 1074 |
| 850440 | स्थैतिक कन्वर्टर्स | 1074 |
| 630260 | टॉयलेट लिनेन और किचन लिनेन, टेरी टॉवेलिंग/इसी तरह के टेरी फैब्रिक्स, कॉटन के | 1044 |
| 630419 | अन्य चादरें | 1013 |
| 90421 | शिमला मिर्च या जीनस पिमेंटा के फल: सुखाया हुआ, न तो कुचला हुआ और न ही पिसा हुआ: | 970 |
| 293399 | केवल नाइट्रोजन हेटेरो एटम (में ) के साथ अन्य हेटेरोसाइक्लिक यौगिक | 930 |
| 300220 | मानव चिकित्सा के लिए टीके | 879 |
| 880330 | हवाई जहाज या हेलीकाप्टर के अन्य भाग | 878 |
| 151530 | अरंडी का तेल और इसके अंश | 848 |
| 720711 | Prdcts Contng By Wt<0.25% Crbn,OfRctnglr (InclSqr)Crs-Sctn;Wdth<TwiceThe Thckns | 842 |
| 520523 | कंबाइंड फाइबर का < 232.56 But >=192.31 Dctx (>43 But <=52 Mtrc No) माप का सिंगल यार्न | 834 |
| 680223 | समतल/समान सतह के ग्रेनाइट सरल रूप से कटा /स्वॉन किया | 824 |
| 401170 | कृषि या वानिकी वाहनों और मशीनों पर प्रयुक्त एक प्रकार का | 814 |
| 293339 | अन्य : पाइरीडीन के संजात : | 807 |
| 320417 | पिगमेंट और उसके आधार पर तैयारी | 785 |
| 630492 | बिना बुने/क्रेच्ड किए हुए कपास की अन्य फर्निशिंग वस्तुएँ | 774 |
| 848180 | अन्य उपकरण : | 768 |
| 290220 | बेंजीन | 755 |
| 760120 | एल्यूमीनियम मिश्र | 739 |

| एच एस कोड | उत्पाद विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 270900 | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज कच्चे तेल से प्राप्त तेल | 59478 |
| 710812 | अन्य कच्चा फॉर्म | 34497 |
| 270119 | अन्य कोयला: | 14421 |
| 710231 | गैर-औद्योगिक हीरे बिना काम किए/सिंपली सॉन क्लीव्ड या ब्रूटेड | 10695 |
| 271111 | तरलीकृत प्राकृतिक गैस | 7881 |

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

| एच एस कोड | उत्पाद विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 851770 | पार्ट्स : | 6982 |
| 710239 | अन्य | 6526 |
| 151110 | कच्चा ताड़ का तेल और इसके अंश | 5676 |
| 880240 | हवाई जहाज और अन्य विमान, जिनका बिना लदा हुआ भार 15000 किलोग्राम से अधिक है | 5368 |
| 847130 | <10 कि.ग्राम वजन वाली पोर्टेबल डिजिटल आटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन, जिसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कीबोर्ड और एक डिस्प्ले होता है। | 5243 |
| 854231 | प्रोसेसर और नियंत्रक, मेमोरी, कन्वर्टर्स, लॉजिक सर्किट, एम्पलीफायर, क्लॉक के साथ संयुक्त हैं या उसके बिना | 5063 |
| 271019 | अन्य पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिज आदि से प्राप्त तेल | 4570 |
| 271113 | लिक्विड ब्यूटेन | 4105 |
| 851762 | रिसेप्शन, रूपांतरण और प्रसारण या आवाज, छवियों या अन्य डेटा के पुनर्जनन के लिए मशीनें, जिसमें स्विट भी शामिल है | 3663 |
| 271112 | तरलीकृत प्रोपेन | 3621 |
| 150710 | डीगम्ड या उसके बिना सोया बीन क्रूड ऑयल | 2837 |
| 310210 | यूरिया जलीय घोल में है या उसके बिना | 2798 |
| 890590 | अन्य वाहन, फायर फ्लोट आदि | 2626 |
| 854239 | अन्य | 2314 |
| 851712 | सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन: | 2244 |
| 854140 | फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर डिवाइस, Photovltc सेल सहित मॉड्यूल्स/ मेड अप इनटू पैनल्स में असेंबल्ड या उसके बिना ; प्रकाश उत्सर्जक डायोड | 2071 |
| 852990 | एचडीजी 8525 से 8528 के अन्य भाग | 2049 |
| 760200 | एल्यूमीनियम अपशिष्ट और स्क्रैप | 2008 |
| 151211 | सूरजमुखी और कुसुम के बीज का कच्चा तेल | 1964 |
| 310530 | डाईमोनम हाइड्रोजन या फॉस्फेट (डाईमोनम फॉस्फेट) | 1949 |
| 852580 | टेलीविजन कैमरा, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर: | 1838 |
| 847150 | सबहेडिंग 847141 और 847149 को छोड़कर डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टॉर्ग/इनपुट/आउटपुट यूनी जैसे एक/दो प्रकार के यूनी में शामिल /नहीं | 1836 |
| 280920 | फॉस्फोरिक एसिड और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड | 1683 |
| 390410 | पॉलीविनाइल क्लोराइड), अन्य के साथ मिश्रित नहीं | 1584 |
| 980100 | प्रोजेक्ट सामान | 1499 |
| 720421 | स्टेनलेस स्टील का अपशिष्ट और स्क्रैप | 1446 |
| 870899 | एचडीजी 8701-8705 के व्हीकल के अन्य पीआरटीएस और एक्सेसर्स | 1359 |
| 284390 | अन्य यौगिक; अमलगम : | 1356 |
| 847330 | एचडीजी नंबर 8471 के मशीन के पार्ट्स और एक्सेसरीज | 1322 |

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

| एच एस कोड | उत्पाद विवरण | मूल्य |
|---|---|---|
| 720449 | अन्य अपशिष्ट और स्क्रैप | 1274 |
| 850440 | स्थैतिक कन्वर्टर्स | 1258 |
| 310420 | पोटेशियम क्लोराइड | 1213 |
| 271012 | लाइट  तेल और उनसे निर्मित : | 1205 |
| 850760 | लिथियम-आयन | 1193 |
| 847989 | एचडीजी 8479 के अन्य मशीन और मैकेनिकल  एप्लाएंस | 1134 |
| 740200 | अपरिष्कृत कॉपर; इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए कॉपर एनोड्स | 1088 |
| 740311 | परिष्कृत कॉप  के कैथोड और कैथोड के अनुभाग | 1026 |
| 270112 | बिटुमेन कोयला चूर्णित/या नहीं, लेकिन एकत्रित नहीं | 1016 |
| 841112 | एक थ्रस्ट के टर्बो-जेट>25 केएन | 1008 |
| 80131 | काजू ताज़ा/खोल में सुखाया हुआ | 985 |
| 740400 | कॉपर अपशिष्ट और स्क्रैप | 930 |
| 848180 | अन्य उपकरण : | 914 |
| 854232 | मेमोरीज | 914 |
| 392690 | प्लास्टिक की अन्य वस्तुएँ | 895 |
| 80211 | बादाम ताजा या सूखे खोल में | 868 |
| 382200 | खाद निदान/प्रयोगशाला अभिकर्मकों को छोड़कर एचडीजी संख्या 3002/3006 का माल | 866 |
| 470790 | अन्य, बिना छांटा अपशिष्ट  और स्क्रैप सहित | 839 |
| 293399 | केवल नाइट्रोजन हेटेरो एटम (S) के साथ अन्य हेटेरोसाइक्लिक यौगिक | 828 |

स्रोत: व्यापार सांख्यिकी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

**डॉ. राहुल नाथ चौधरी**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद में रिसर्च फेलो थे। उनकी प्राथमिक अनुसंधान रुचियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, भू-अर्थशास्त्र और डिजिटल व्यापार शामिल हैं। राहुल को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अकादमिक और उद्योग में विभिन्न पदों पर  काम करने का एक दशक का लंबा अनुभव है। उन्होंने 2021 में रूटलेज द्वारा प्रकाशित पुस्तक, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ, का संपादन किया है। उन्होंने कई पुस्तक अध्यायों और अकादमिक पत्रिकाओं में योगदान दिया है। राहुल नियमित रूप से विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों पर ओपिनियन पीस और कमेंट्री लिखते हैं।

SAPRU HOUSE PAPER

Indian Council of World Affairs

Sapru House, Barakhamba Road, New Delhi- 110 001, India
T: +91-11-2331 7246-49 | F: +91-11-2331 1208

www.icwa.in